EDU TERIA
E - D.N.A
Daily Newspaper Analysis
Prelims Mains Essay
Useful For Prelims
Date: 17-Nov-2025

20 को 10वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश

कल राजग विधायक दल की बैठक में होगी नाम की औपचारिक घोषणा, गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह

राज्य ब्यूरो, जागरण ● पटना : बिहार में राजग की प्रचंड जीत के बाद नीतीश कुमार रिकार्ड दसवीं बार 20 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। सोमवार को 11.30 बजे से कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें सरकार के इस्तीफे का प्रस्ताव पास किया जाएगा। इसके बाद नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलकर त्यागपत्र देंगे और नई सरकार के गठन का दावा पेश करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह गुरुवार को ऐतिहासिक गांधी मैदान में होने की संभावना है। समारोह में पीएम नरेन्द्र मोदी भी शामिल होंगे। रविवार को 18वीं विधानसभा गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस बीच जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) बनाकर विधानसभा चुनाव में कूदने वाले तेज प्रताप यादव ने राजग सरकार को नैतिक समर्थन देने की घोषणा की है।

शनिवार और रविवार को एनडीए के कई विधायक और वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। विधायक दल से लेकर पार्टी संगठन तक, सभी स्तरों पर नेतृत्व ने नीतीश कुमार से मुलाकात की और नवनिर्वाचित विधायकों ने उन्हें बधाई दी। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय व रालोमो नेता उपेंद्र कुशवाहा भी सीएम हाउस पहुंचे। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा को जदयू विधायकों को मुख्यमंत्री से मिलाने का जिम्मा सौंपा गया है। मुलाकातों का यह सिलसिला महज औपचारिकता नहीं, बल्कि नई सरकार के खाके को अंतिम रूप देने की दिशा में एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। इसके बाद नीतीश कुमार राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां को वर्तमान सरकार का इस्तीफा देकर सरकार गठन का दावा पेश करेंगे। इससे पहले चुनाव आयोग ने राज्यपाल को नवनिर्वाचित विधायकों की सूची सौंप दी है। मंगलवार को एनडीए विधायक दल की बैठक होनी है। जिसमें गठबंधन औपचारिक रूप से नीतीश कुमार को अपना नेता घोषित करेगा। एनडीए विधायक दल की बैठक के पूर्व जदयू सोमवार को ही विधायकों की बैठक कर लेगा।

सरकार गठन से पहले दिल्ली में भी राजनीतिक हलचल तेज है। जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह की भाजपा दिग्गजों के साथ बैठक के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा व केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को भी बैठक के लिए दिल्ली में रहने को कहा गया है।

पीएम भी आएंगे

- आज 11.30 बजे मंत्रिमंडल की बैठक, सरकार का स्वरूप तय करने को चला मंथनों का दौर
- शीर्ष नेता दिल्ली में डटे, मांझी और कुशवाहा को दिल्ली रोका गया, नीतीश से मिले कई नेता

बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पुष्पगुच्छ भेंटकर शुभकामनाएं देते केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ● ऐ

शपथ ग्रहण समारोह के लिए 17 से 20 तक गांधी मैदान में आमजन के लिए प्रवेश बंद

जागरण संवाददाता, पटना : नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 20 नवंबर को गांधी मैदान में होगा। इसमें प्रधानमंत्री समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसे देखते हुए 17 से 20 नवंबर तक आमजनता का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। डीएम डा. त्यागराजन एसएम ने रविवार को इस बाबत निर्देश जारी किए हैं।

Dainik Jagaran Page No-1

महिलाओं ने 2005 के बाद बिहार में राजनीति की दिशा बदल दी

■ कौशलेंद्र मिश्र

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव में 2005 के चुनाव के बाद लगातार महिला मतदाताओं को वोट प्रतिशत बढ़ता गया। महिलाओं ने बिहार की राजनीति की दिशा बदल दी है।

कोरोना काल के दौरान 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में महिलाओं के मतदान प्रतिशत में हुई मामूली कमी को अपवाद मान लें तो 2005 के अक्तूबर के बाद हरेक चुनाव में महिलाओं के मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी देखी गई है। महिलाएं सरकार के गठन की मुख्य कारक बनती गईं। राज्य की आधी आबादी को नजरअंदाज करना मुश्किल होता गया। इसके साथ ही, राज्य के विकास के लिए महिलाओं के लिए आरक्षण, महिला केंद्रित योजनाओं का निर्माण और महिलाओं के लिए विभिन्न सुविधाओं पर अमल होता गया। वर्ष 2010 के चुनाव में 2005 अक्तूबर के चुनाव की तुलना में महिलाओं के मतदान प्रतिशत में 10 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई। जबकि, 2015 के चुनाव में 2010 के चुनाव की तुलना में महिलाओं के मतदान प्रतिशत में 5.99 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। 2025 के विधानसभा चुनाव में 2020 में हुए चुनाव के मुकाबले में महिलाओं के मतदान प्रतिशत में 12.11 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

60 .48% महिला वोटर अपने घरों से वोट करने निकली थीं 2015 में

- मतदान प्रतिशत में चुनावदर चुनाव बढ़ोतरी हुई
- इस बढ़ोतरी के कारण एनडीए को लाभ हुआ
- महिलाओं के विकास को केंद्रित कर बनी योजनाएं

वर्षवार महिलाओं का मतदान प्रतिशत

विस चुनाव	वोट प्रतिशत	वृद्धि
2005 फरवरी	42.52	--
2005 अक्तूबर	44.49	+1.97
2010	54.49	+10.00
2015	60.48	+5.99
2020	59.69	-0.89
2025	71.8	+12.11

2010 के चुनाव में महिलाओं के 52.47% वोट पड़े थे

2010 के बाद के विधानसभा चुनावों में महिलाओं ने नीतीश सरकार के लिए जमकर वोटिंग की। 2010 के इस चुनाव में कुल 52.47 प्रतिशत वोट पड़े थे जिसमें महिलाओं का अनुपात 54.49 प्रतिशत का था। जबकि पुरुष का मत प्रतिशत 51.12 फीसदी ही थी। यानी महिलाओं ने पुरुषों को वोटिंग के मामले में मात दे दी थी। 2015 के विधानसभा चुनाव में महिलाएं एक बार फिर जमकर वोट करने अपने-अपने घरों से बाहर निकलीं। इस चुनाव में 56.66 प्रतिशत वोट पड़े थे। इस चुनाव में 60.48 प्रतिशत महिला वोटर अपने घरों से वोट करने निकली थीं। जबकि, पुरुष वोटर इस बार भी पिछड़ गए थे और उनका वोट प्रतिशत 53.32 प्रतिशत ही रहा। हालांकि, इस बार के चुनाव में राज्य में महागठबंधन की सरकार बनी थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में महिला वोटर की तादाद में थोड़ी कमी तो जरूर आई लेकिन फिर वे पुरुषों के मुकाबले काफी ज्यादा था। इस चुनाव में कुल 56.93 प्रतिशत वोट पड़े थे।

Hindustan Page No-1

अमेरिका में भारतीय ग्रीन कार्ड आवेदकों को राहत

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी विदेश विभाग ने दिसंबर, 2025 के लिए वीजा बुलेटिन जारी किया है। इसमें परिवार आधारित और रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड श्रेणियों में भारतीय आवेदकों के लिए राहत दी गई है।

■ विदेश विभाग ने दिसंबर, 2025 के लिए वीजा बुलेटिन जारी किया

परिवार-आधारित वीजा वाले लोगों के लिए कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। इसलिए उन्हें अभी और इंतजार करना होगा। वहीं, रोजगार-आधारित श्रेणियों के लिए भारत के लिए सभी प्रमुखतिथि आगे बढ़ गई हैं।ईबी-1 एक महीने आगे बढ़कर 15 मार्च, 2022 हो गई है। ईबी-2 एक महीने और 14 दिन आगे बढ़कर 15 मई, 2013 हो गई है और ईबी-3 एक महीने आगे बढ़कर 22 सितंबर, 2013 हो गई है। इसका मतलब है कि इन श्रेणियों में आने वाले भारतीय आवेदक अब ग्रीन कार्ड की अंतिम मंजूरी के और करीब पहुंच रहे हैं। ईबी-4 और धार्मिक कर्मचारी दोनों श्रेणियों में वृद्धि हुई है। वहीं, ईबी-5 अनारक्षित श्रेणी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। परिवार-आधारित श्रेणी में लगभग कोई बदलाव नहीं हुआ है। एफ1, एफ2ए, एफ2बी, एफ3, एफ4 इन सभी श्रेणी में अंतिम कार्रवाई तिथि में कोई भी प्रगति नहीं हुई है।

परेशानी | 31 देशों के साथ भारत ने किया है अदला-बदली का प्रावधान, विदेशी जेलों में अभी 10 हजार से ज्यादा भारतीय कैदी, प्रत्यावर्तन अधिनियम कानून ज्यादा प्रभावी नहीं होने से दिक्कत

विदेशी जेलों से भारतीय कैदियों की वापसी में कई तरह की अड़चनें

■ मदन जैड़ा

नई दिल्ली। विदेशी जेलों में इस समय 10 हजार से ज्यादा भारतीय कैदी हैं। उन्हें लाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कई पहल की गई हैं, लेकिन जो कैदी सजा काट रहे हैं, उन्हें वापस लाने में अड़चनें पैदा हो रही हैं।

इसके चलते ऐसे कैदियों को शेष सजा भारत में काटने का प्रावधान करने वाला कानून ज्यादा प्रभावी साबित नहीं हुआ है। अभी इसकी समीक्षा पर विचार हो रहा है।

दरअसल, प्रत्यावर्तन अधिनियम के तहत कैदियों की अदला-बदली का प्रावधान है। यह कानून भारत से कैदियों को उनके देशों में जाने और दूसरे देशों से भारत लाने की अनुमति प्रदान करता है। इस कानून के तहत अब तक 31 देशों के साथ भारत ने करार किए हैं, जिनमें संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और सऊदी अरब भी शामिल हैं। इनकी जेलों में भारत के सबसे ज्यादा कैदी हैं। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, इस कानून के तहत साल में दो-चार कैदियों की ही वापसी हो पाती है।

82 देशों की जेलों में मौजूद कैदी: विदेश मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार, अभी 82 देशों की जेलों में भारत के 10,574 कैदी हैं। इनमें 40 फीसदी विचाराधीन कैदी होने का अनुमान है। 43 ऐसे कैदी हैं, जिन्हें मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। यूएई, सऊदी अरब और नेपाल देशों के साथ कैदियों की वापसी का समझौता भी है। इस साल यूएई ने 500 तथा सऊदी अरब ने 850 कैदियों को रमजान के मौके पर रिहा किया था। हालांकि, इनमें ज्यादातर ऐसे कैदी थे, जो सजा पूरी कर चुके थे, या करने जा रहे थे या फिर जो छोटे-मोटे मामलों में जेल में थे। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2010 से अब तक 10 हजार से ज्यादा लोगों को विदेशी जेलों से वापस लाया जा चुका है।

समझौते के तहत सबसे ज्यादा मछुआरे लौटे

विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2010 से अब तक 10 हजार से ज्यादा लोगों को विदेशी जेलों से वापस लाया गया। हालांकि, इनमें सबसे ज्यादा संख्या मछुआरों की है, जो श्रीलंका और पाकिस्तान से विभिन्न पारस्परिक समझौतों के तहत वापस लौटे हैं।

31 देशों के साथ भारत ने किया है कैदियों की अदला-बदली का प्रावधान

क्या हैं दिक्कतें

1. कैदियों के बदले वापसी के लिए कैदी उपलब्ध नहीं होना
2. कई बार विदेशी से कैदी खुद भी भारत नहीं आना चाहता
3. कई मामलों में नागरिकता के दस्तावेजों की पुष्टि नहीं हो पाती
4. कैदियों की रिहाई नहीं होती, बाकी सजा देश की जेल में काटना होता है
5. कानून के तहत उन्हीं कैदियों को ला सकते हैं, जिन्हें अंतिम सजा सुनाई गई है। विचाराधीन कैदियों को यह कानून कवर नहीं करता

किस देश में कितने कैदी

यूएई	2,773
सऊदी अरब	2,379
नेपाल	1,357
मलेशिया	380
कुवैत	342
ब्रिटेन	323
बहरीन	261
पाकिस्तान	246
चीन	183
अमेरिका	175

Hindustan Page No-15

दुनियाभर में सोशल मीडिया से युवाओं का हो रहा मोह भंग

अध्ययन

न्यूयॉर्क, एजेंसी। फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, यू-ट्यूब जैसे सोशल मीडिया पर घंटों बिताने वाले लोगों का अब इस मंच से मोह भंग हो रहा है। इसमें ज्यादातर युवा शामिल हैं, जो इनसे धीरे-धीरे दूरी बना रहे हैं। अमेरिकी कंपनी डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स ने यह अध्ययन किया है। उन्होंने कई देशों के 2.5 लाख लोगों पर किए गए अध्ययन में यह जानने का प्रयास किया कि आखिर लोग सोशल मीडिया और इंटरनेट पर अपना समय क्यों कम कर रहे हैं।

ये हैं बड़ी वजहें

1. एआई से भरी फालतू सामग्री से परेशान हैं
2. सोशल मीडिया की खराब गुणवत्ता से तंग आ चुके हैं
3. बिना मतलब की सलाहें देखकर परेशान हैं
4. झगड़ा बढ़ाने वाले कंटेंट से दूर रहना चाहते हैं
5. बोरियत को फिर से एक अच्छी चीज की तरह अपनाना चाहते हैं

अकाउंट भी कर रहे डिलीट: शोधकर्ताओं ने पाया कि फालतू सामग्री, खराब होती गुणवत्ता और बिना मतलब की सलाह से वे परेशान हो चुके हैं, इसलिए वे सोशल मीडिया का कम इस्तेमाल कर रहे हैं या कई अकाउंट्स भी डिलीट कर रहे हैं। अध्ययन के अनुसार, दुनियाभर में सोशल मीडिया पर बिताया गया समय 2022 में सबसे ज्यादा था। लेकिन, 2024 तक यह समय लगभग 10 प्रतिशत कम हो गया। अध्ययन में पाया गया कि विकसित देशों में लोग औसतन दो घंटे 20 मिनट रोज सोशल मीडिया पर बिताते हैं। सबसे ज्यादा कमी युवा लोगों में देखी गई है।

भारत में भी लोग बिता रहे कम समय

कॉमस्कोर इंक. की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय यूजर्स ने जून 2024 में सोशल मीडिया पर लगभग 10 बिलियन घंटे बिताए जो जून 2023 में 11 बिलियन घंटे थे। यह लगभग 10% की गिरावट को दर्शाता है। रिपोर्ट के अनुसार, जून 2023 में सोशल मीडिया पर 486 मिलियन सक्रिय यूजर थे, जो जून 2024 में मामूली रूप से घटकर 485 मिलियन रह गए। सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से चिंता, अवसाद जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति जागरुकता बढ़ने के कारण भी यूजर अपने उपयोग को सीमित कर रहे हैं।

2022 में सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा समय बिताया गया

2024 तक यह समय लगभग 10% कम हो गया

2.5 लाख लोगों को दुनिया के 50 देशों से अध्ययन

■ विकसित देशों में लोग रोज औसतन दो घंटे 20 मिनट का समय बिताते हैं

Hindustan Page No-16

तैयारी | इसरो प्रमुख वी नारायणन ने दी लक्ष्यों की जानकारी, इस साल सात और प्रक्षेपण करेगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन

इसरो भारत में अंतरिक्ष यान निर्माण को तीन गुना बढ़ाएगा

अच्छी खबर

कोलकाता, एजेंसी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष वी. नारायणन ने कहा कि इसरो तीन साल में वार्षिक अंतरिक्ष यान उत्पादन को तिगुना करने पर काम कर रहा है। कहा कि अंतरिक्ष एजेंसी चालू वित्त वर्ष के अंत से पहले सात प्रक्षेपणों का लक्ष्य है। भारतीय उद्योग द्वारा निर्मित पहले पीएसएलवी का प्रक्षेपण मील का पत्थर बनेगा।

2035 तक खुद का अंतरिक्ष स्टेशन

नारायणन ने कहा कि इसरो ने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन पर काम शुरू कर दिया है, जिसे 2035 तक पूरा करने का लक्ष्य है। पांच मॉड्यूल में पहला 2028 तक कक्षा में स्थापित कर देंगे। इससे भारत अंतरिक्ष स्टेशन वाला तीसरा देश बन जाएगा। अमेरिका के नेतृत्व वाला अंतरिक्ष स्टेशन अंतिम चरण में है और चीन के तियांगोंग में संचालन शुरू हो गया है।

2027 में पहला मानव मिशन

पहले मानव-अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान को लेकर नारायणन ने कहा कि केवल मानवरहित मिशनों की समय-सीमा बदली है। मानवयुक्त मिशन की योजना 2027 के लिए बनी थी, जिसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के साथ पहली उड़ान से पूर्व तीन मानवरहित परीक्षण मिशन होंगे।

2040 में चंद्रमा पर उतरेंगे भारतीय अंतरिक्ष यात्री

इसरो प्रमुख ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसरो को भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर भेजने और 2040 तक उन्हें सुरक्षित वापस लाने की दिशा में काम का भी निर्देश दिया है। बताया कि अमेरिका आर्टेमिस के तहत चंद्र मानवयुक्त मिशन की योजना बना रहा है जबकि चीन ने अपने पहले मानवयुक्त चंद्र अभियान के लिए 2030 का लक्ष्य रखा है।

आठ फीसदी हिस्सेदारी का लक्ष्य

वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी वर्तमान में लगभग दो प्रतिशत है और इसरो 2030 तक इसे आठ प्रतिशत करने पर काम कर रहा है। इसरो प्रमुख ने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का वर्तमान मूल्य करीब 8.2 अरब अमेरिकी डॉलर है और 2033 तक 44 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है। वर्तमान में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 630 अरब अमेरिकी डॉलर है।

Hindustan Page No-13

दुश्मन के ड्रोन को दो किलोमीटर दूर से मार गिराएगी लेजर बीम

सेना व वायुसेना के लिए 16 प्रणालियों की होगी खरीद, डीआरडीओ ने किया है विकसित

नई दिल्ली, एएनआइ : आपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी सेना ने भारत के विरुद्ध बड़ी संख्या में ड्रोन का इस्तेमाल किया था। इसके मद्देनजर भारतीय सेनाएं दुश्मन के ड्रोन के विरुद्ध अपनी क्षमताओं को और मजबूत बना रही हैं। इसके लिए थलसेना और वायुसेना 16 स्वदेशी 'ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम' के आर्डर देने जा रही हैं। यह प्रणाली दो किलोमीटर दूर से दुश्मन के ड्रोन को लेजर बीम से मार गिराने और उन्हें निष्क्रिय करने में सक्षम है।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के इस इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम (मार्क 2) को रक्षा मंत्रालय जल्द मंजूरी दे सकता है। रक्षा अधिकारियों ने बताया कि 10 किलोवाट की लेजर बीम से दुश्मन ड्रोन को मार गिराने की दूरी दोगुनी हो जाएगी। इससे पहले की प्रणाली सिर्फ एक किलोमीटर की दूरी तक ही दुश्मन ड्रोन को निशाना बनाने में

10 किलोवाट की लेजर बीम का होगा उपयोग पहले एक किलोमीटर थी मारक क्षमता

कुरनूल में प्रदर्शित हवाई लक्ष्यों को मार गिराने वाला डीआरडीओ द्वारा विकसित लेजर हथियार। फाइल/एएनआइ

सक्षम थी। इसमें दो किलोवाट की लेजर बीम का इस्तेमाल किया जाता था।

पांच किलोमीटर की मारक क्षमता का हो रहा परीक्षण: डीआरडीओ दरअसल लगातार लंबी दूरी की लेजर-आधारित ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरसेप्शन सिस्टम्स को विकसित कर रहा है। विकास के इस क्रम में उसने डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम का सफल परीक्षण किया है, जो पांच किलोमीटर की दूरी तक की प्रणालियों को निशाना बना सकता है। वह भारतीय सेना की भागीदारी से अपने परीक्षण जारी रखे हुए है। पांच किलोमीटर की मारक क्षमता 30 किलोवाट के लेजर-आधारित डायरेक्ट एनर्जी वेपन से हासिल की जाएगी।

और में हुआ था परीक्षण : डीआरडीओ की एक प्रयोगशाला सेंटर फार हाई एनर्जी सिस्टम्स एंड

ऐसे काम करती है प्रणाली

लेजर आधारित यह प्रणाली दुश्मन ड्रोन के किसी कमजोर हिस्से जैसे- मोटर या बैटरी पर हाई एनर्जी लेजर से निशाना बनाती है। इसकी तीव्र ऊष्मा प्लास्टिक को पिघला देती है, तारों को जला देती है या महत्वपूर्ण इलेक्ट्रानिक कलपुर्जों को नुकसान पहुंचा देती है। इससे ड्रोन निष्क्रिय हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है।

साइंसेज (चेस) ने आंध्र प्रदेश के कुरनूल में अप्रैल में पहली बार 30 किलोवाट के लेजर-आधारित वेपन सिस्टम (डीईडब्ल्यू एमके-2ए) का उपयोग करके फिक्स्ड-विंग वाले विमानों, मिसाइलों और स्वार्म ड्रोनों को मार गिराने की क्षमता प्रदर्शित की थी।

अमेरिका, चीन और रूस के पास है क्षमता: 30 किलोवाट के लेजर-आधारित वेपन सिस्टम का परीक्षण करके भारत चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया है। वर्तमान में इस तरह की क्षमता सिर्फ अमेरिका, चीन और रूस जैसों देशों के पास ही है।

अन्य हाई-एनर्जी सिस्टम्स पर भी चल रहा काम: डीआरडीओ प्रमुख डा. समीर वी. कामत ने पूर्व में कहा भी था कि डीआरडीओ अन्य हाई-एनर्जी सिस्टम्स पर भी काम कर रहा है। इनमें हाई-एनर्जी माइक्रोवेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस और कई तकनीकें शामिल हैं जो स्टार वार्स जैसी क्षमता प्रदान करेंगी।

एकीकृत कमान में तीनों सेनाओं की सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल किया जाएगा : सीडीएस

नई दिल्ली, प्रेट : चीफ आफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने सशस्त्र बलों के एकीकरण की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा है कि इस प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक सेना अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाए रखेंगी और एकीकृत कमान में उनकी सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल किया जाएगा। सीडीएस ने शनिवार को आयोजित एक कार्यक्रम में हाल में हुए आपरेशन सिंदूर का भी उदाहरण दिया। इस आपरेशन के दौरान तीनों सेनाओं-थलसेना, नौसेना और वायुसेना ने अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया। जनरल चौहान ने रक्षा थिंक-टैंक यूएसआइ (यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन) द्वारा 14 एवं 15 नवंबर को आयोजित दो दिवसीय भारतीय सैन्य विरासत उत्सव में भाग लिया। उन्होंने अपनी नई पुस्तक 'रेडी, रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट 2: शेपिंग ए फ्यूचर रेडी फोर्स' पर केंद्रित संवाद के दौरान संकेत दिया कि जल्द ही इसका तीसरा खंड भी

नई दिल्ली में भारतीय सैन्य विरासत उत्सव के दौरान अपने विचार व्यक्त करते सीडीएस जनरल अनिल चौहान● एएनआइ

आ सकता है, जिसमें आपरेशन सिंदूर संबंधी विवरण भी होंगे। तीनों सेनाओं में एकजुटता हासिल करने के सरकार के दृष्टिकोण के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के बाद की गई भारत की सैन्य कार्रवाई और इन स्टीक हमलों से पहले के दिनों के कुछ उदाहरण दिए। जनरल चौहान ने कहा कि एकीकरण के दृष्टिकोण के अनुरूप प्रयास जारी हैं। लेकिन, प्रत्येक सेवा अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाए रखेगी।

Dainik Jagaran Page No-8

अमेरिकी छूट से भारत को 25 हजार करोड़ तक का निर्यात लाभ होगा

अनुमान

नई दिल्ली, एजेंसी। अमेरिका ने 250 से अधिक खाद्य उत्पादों पर आयात शुल्क घटाने का फैसला किया है, जिनमें 229 कृषि वस्तुएं शामिल हैं। इस फैसले भारत के किसानों और निर्यातकों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। अनुमान है कि इस फैसले से भारत के 2.5-3 अरब डॉलर (लगभग 20,000 से 25,000 करोड़ रुपये) तक के निर्यात को सीधा फायदा मिलेगा।

यह राहत इसलिए अहम है क्योंकि अमेरिकी शुल्क बढ़ने से भारत के निर्यात पर भारी असर पड़ा है। अब शुल्क घटने से भारतीय निर्यात में

250 से अधिक खाद्य वस्तुओं से शुल्क हटा दिया है अमेरिकी प्रशासन ने

12 फीसदी की गिरावट आई थी भारतीय निर्यात में 50% शुल्क के चलते

दोबारा तेजी आने की संभावना जताई जा रही है। भारत अमेरिका को थाइम को छोड़कर लगभग सभी मसाले, चाय, कॉफी, काजू और कई फल-सब्जियां निर्यात करता है। इनमें भारत की अच्छी हिस्सेदारी है लेकिन ट्रंप प्रशासन द्वारा 50 फीसदी शुल्क लगाने के बाद ये क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुए। कृषि निर्यात नीति से जुड़े अधिकारियों के अनुसार यह कदम भारतीय किसानों और कृषि निर्यातकों को तुरंत लाभ पहुंचाएगा।

इन क्षेत्रों को फायदा

भारतीय निर्यात संगठन महासंघ (फियो) के महानिदेशक अजय सहाय ने कहा कि इस छूट से करीब तीन अरब डॉलर तक के निर्यात को लाभ मिलेगा। अमेरिका द्वारा दी गई नई टैरिफ छूट का सबसे ज्यादा लाभ भारतीय कृषि उत्पादों, खासकर उच्च-मूल्य वाले प्रीमियम उत्पादों को होगा। विशेषज्ञों के अनुसार, मसाले, काली मिर्च, इलायची, जीरा, अदरक, हल्दी और फलों के उत्पाद जैसे उच्च-मूल्य वाले क्षेत्रों को इसका मुख्य फायदा होगा।

सभी क्षेत्रों में राहत नहीं

हालांकि, सभी क्षेत्रों में लाभ समान नहीं होगा। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के संस्थापक अजय श्रीवास्तव का कहना है कि भारत को सीमित श्रेणियों में ही इस फैसले का फायदा मिलेगा, क्योंकि जिन वस्तुओं पर टैरिफ छूट का असर सबसे ज्यादा है-जैसे टमाटर, खट्टे फल, खरबूजे, केले और फलों के रस, इनमें भारत की अमेरिकी बाजार में पकड़ कमजोर है। उन्होंने कहा कि मसालों और विशिष्ट बागवानी उत्पादों में जरूर थोड़ी मजबूती आएगी और टैरिफ बढ़ने के बाद जो मांग घटी थी, वह दोबारा लौट सकती है।

भारत से अमेरिका को मसालों का निर्यात 35.8 करोड़ डॉलर और चाय-कॉफी उत्पादों का मूल्य 8.2 करोड़ डॉलर से अधिक है।

इसलिए हटाना पड़ा शुल्क

ट्रंप प्रशासन ने यह कदम घरेलू महंगाई को काबू में रखने के लिए उठाया गया है। इससे पहले ट्रंप प्रशासन दावा करता रहा है कि टैरिफ के कारण कीमतों में बढ़ोतरी नहीं होती है लेकिन स्थानीय स्तर पर बढ़ती महंगाई लगातार मुद्दा बनती जा रही थी। लोगों को राहत देने के लिए ट्रंप ने आदेश जारी किया है।

भारत पर पड़ा था असर

इससे पहले, अप्रैल में लगाए गए 50 प्रतिशत तक के शुल्कों के कारण भारत के निर्यात में बड़ी गिरावट आई थी और सितंबर में यह 12 प्रतिशत घटकर 5.43 अरब डॉलर पर आ गया था। ट्रंप प्रशासन ने जहां इंडोनेशिया और वियतनाम पर 20% से कम शुल्क लगाया था, वहीं भारत पर 50 प्रतिशत शुल्क थोपा था।

Hindustan Page No-13

राष्ट्रीय मिर्गी दिवस | **एसकेएमसीएच पहुंच रहे मिर्गी के मरीज, 20-30 वर्ष तक के युवा आ रहे हैं चपेट में**

मोबाइल का इस्तेमाल युवाओं को दे रहा मिर्गी का मर्ज

■ मृत्युंजय

मुजफ्फरपुर। मोबाइल का इस्तेमाल लोगों को मिर्गी का मरीज बना रहा है। 20 से 30 वर्ष तक के युवा इसकी चपेट में आ रहे हैं। श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज के न्यूरो विभाग में लगातार ऐसे मरीज इलाज के लिए ओपीडी में पहुंच रहे हैं। श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज में न्यूरो विभागाध्यक्ष डॉ. दीपक कर्ण ने बताया कि मोबाइल से निकलने वाली फिल्क्सिन लाइट से दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो रहा है, जिससे कम उम्र के लोगों में मिर्गी की शिकायत आ रही है। बताया कि मोबाइल में लगातार लाइट कम ज्यादा होती रहती है, जिससे दिमाग में तरंगें उठती हैं और नसों पर खतरा बढ़ता है। कहा कि मिर्गी से बचाव के लिए मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करना जरूरी है और रात में पूरी नींद लेना अनिवार्य है। डॉ. कर्ण ने बताया कि मिर्गी तीन तरह की होती है। पहली सामान्य मिर्गी, जिसमें दोनों हाथ और शरीर कांपते हैं। दूसरी फोकल मिर्गी, जिसमें शरीर का एक हिस्सा कांपता है और तीसरा ड्रॉप अटैक, जिसमें अचानक व्यक्ति गिर जाता है। मुजफ्फरपुर और उत्तर बिहार में सामान्य मिर्गी के मरीज अधिक हैं।

बुजुर्गों में सोडियम कम होने से आ रहा अटैक : एकसेएमसीएच की ओपीडी में आने वाले बुजुर्गों में सोडियम के कम होने से मिर्गी का अटैक देखने को मिलता है। डॉ. दीपक कर्ण ने बताया कि मिर्गी की जांच के लिए हमलोग सिटी स्कैन, एमआरआई और ईईजी जांच कराते हैं। इसके बाद मरीज का इलाज शुरू किया जाता है।

प्रसव के समय संक्रमण से बच्चों को हो रही मिर्गी

श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज के न्यूरो विभाग के डॉ. मयंक ने बताया कि प्रसव के समय संक्रमण से बच्चों में मिर्गी के मामले आ रहे हैं। एसकेएमसीएच की ओपीडी में आने वाले इन बच्चों की उम्र 10 साल से कम है। बताया कि हर दिन औसतन दो से तीन बच्चे मिर्गी की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। कई केस में देखने को मिला है कि बच्चों के पेट में कीड़े के संक्रमण और कीड़े के दिमाग में चढ़ जाने से बच्चों में यह बीमारी होती है। इसके अलावा कई बच्चों में जन्मजात मिर्गी के कारण मिल रहे हैं। जन्म के समय ऑक्सीजन नहीं मिलने से उन्हें मिर्गी की बीमारी हो जाती है। मिर्गी का इलाज तीन साल तक होता है। मिर्गी की दवा बीच में छोड़ देने से नुकसान हो जाता है।

इस बीमारी के लक्षण

- हाथ में कंपन
- जीभ का कट जाना
- मुंह से लार निकलना
- अचानक गिर जाना
- बेहोश होना
- आंख ऊपर उलट जाना
- कपड़े में पेशाब हो जाना

Hindustan Page No-12

संभावनाओं के नए द्वार खोलता एआई

पिछले दिनों अनुराग बेहर ने एक लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने एआई की तुलना ड्रग्स से की थी और इसे बच्चों के लिए नुकसानदेह बताया था। मेरी राय में यह काफी अतिरंजित सोच है। तकनीक को शिक्षा का हिस्सा बनाना चाहिए या नहीं, इस पर चर्चा ही बेमानी है, क्योंकि तकनीक अब शिक्षा व्यवस्था का अभिन्न अंग बन चुकी है। इसे हम कितना नकारेंगे और कहां तक नकारेंगे? क्या हम लैपटॉप बंद कर देंगे या मोबाइल? सोशल मीडिया बंद करेंगे या ई-मेल? अब कोई भी एप या पोर्ट एकाकी नहीं है। अगर एक पोर्ट या एप आप उपयोग कर रहे हैं, तो वह तमाम तरह की सूचनाएं संकलित कर रहा है और उनको अन्य माध्यमों के साथ साझा करके अपनी क्षमता बढ़ा रहा है।

साफ है, हमें तकनीक के चयनात्मक विरोध से बचना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने विश्वविद्यालय में तकनीक को अपनाएं, मगर स्कूलों में, वंचित समाज में तकनीक के प्रसार का विरोध करें। तकनीक का विरोध एक वर्ग के लिए सौंदर्य मूल्य का विषय हो सकता है, मगर वंचित वर्ग के लिए वही तकनीक आवश्यकता का विषय हो सकती है, जो उनकी प्रतिस्पद्धात्मकता को बढ़ा सकती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का दुनिया के कई हिस्सों में अलग-अलग कारणों से विरोध होता रहा है। कुछ देश इसको बहुत शुरुआती अवस्था में बच्चों को नहीं सिखाने की बातें कह रहे हैं, तो कुछ इससे जुड़े निजता के अधिकार के सवाल उठा रहे हैं, मगर बेहर के लेख में बताया गया था कि एआई हमारी सोचने की क्षमता को खत्म कर रहा है और इससे बचने का एकमात्र उपाय है- एआई का इस्तेमाल रोकना, जो कतई संभव नहीं है।

हम उपेक्षा करके तकनीक से नहीं लड़ सकते। अगर हमें लड़ना है, तो पहले तकनीक को समझकर उसका सकारात्मक इस्तेमाल करना होगा। इतना ही नहीं, एआई केवल उन नौकरियों को ही खत्म कर सकता है, जो बहुत ज्यादा सूचनात्मक या निर्देशात्मक हों। जहां कई स्तर पर निर्णय लेने की बात हो या जहां परिस्थितियों के अनुसार फैसले लेने की संभावना हो, वहां इंसानों से बेहतर एआई नहीं है। इसलिए, एआई को खलनायक या अफीम आदि बताने के बजाय हमें उसके सही उपयोग के बारे में सोचना चाहिए।

अगले साल जब भारत एआई समिट आयोजित करने जा रहा है और पूरा विश्व हमें आशा भरी निगाह से देख रहा है, तब इस तरह की निराशाजनक बातें करने का कोई औचित्य नहीं। इसके उलट हमें एआई के मानव-जीवन में बेहतर उपयोग को लेकर अपनी योजना विश्व के सामने रखनी चाहिए।

रामानंद, शिक्षाविद

अनुलोम-विलोम
शिक्षा में एआई

इससे जुड़े खतरे कभी कम नहीं होंगे

इन दिनों शैक्षणिक संस्थानों में जो कुछ हो रहा है, वह शोचनीय है। शिक्षण संस्थानों का मूल उद्देश्य छात्रों में सोचने की क्षमता विकसित करना है। मगर अब एआई के इस्तेमाल के बाद इसका उल्टा हो सकता है। हो भी रहा है। दरअसल, अब सोचने की जिम्मेदारी एआई को दी जा रही है। यह शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम, शिक्षण योजना, पाठ्य-पुस्तकें, असाइनमेंट व परीक्षा के प्रश्न-पत्र तक तैयार कर रहा है और छात्र भी जवाब तैयार करने के लिए एआई का इस्तेमाल करने लगे हैं। यह एक तरह का धोखा है। शिक्षा का खत्म होना एआई से मिलने वाला पहला खतरा है, इसलिए अब दुनिया के कई संवेदनशील संस्थान और शिक्षक एआई के खिलाफ दृढ़ हो गए हैं। निस्संदेह, मौजूदा डिजिटल दुनिया में एआई को रोक पाना नामुमकिन है, मगर बीते कुछ वर्षों में इसमें हुई प्रगति बता रही है कि इसकी एक बड़ी लहर आने वाली है। इसलिए, शिक्षक शिक्षण के पुराने तरीकों पर जोर देने लगे हैं, यानी कक्षा में आमने-सामने बैठकर पढ़ाई पर उनका ध्यान बढ़ गया है। यह समझना होगा कि ईसानी गतिविधियों में एआई से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए कोशिशें करनी होंगी। एक तरह से शिक्षा में इसका इस्तेमाल प्रतिबंधित कर देना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, तो इसका मतलब होगा कि हम नौजवानों को एआई रूपी नशे का आदी बना रहे हैं। यह पारंपरिक मादक पदार्थों से भी ज्यादा खतरनाक नशा है। हमें अपने भविष्य को इससे बचाना होगा।

जे लाल, शिक्षाविद

तकनीक के अत्यधिक इस्तेमाल से लोगों की मानसिक क्षमता में ह्रास हो रहा है, यह समझने के लिए हमें किसी अध्ययन की जरूरत नहीं है। इसका पता कोई भी आम आदमी लगा सकता है। मिसाल के तौर पर, टेलीफोन नंबर द्वारा। जब बेसिक फोन का जमाना था और उंगलियां बटन पर दबाई जाती थीं, तब हमें कई नंबर याद होते थे। मगर जैसे ही मोबाइल का जमाना आया और सब कुछ एक बटन में सिमट गया, तो हम नंबर भूलने लगे। हमें अब अपने परिजनों तक के नंबर याद नहीं रहते। शिक्षा में एआई के अत्यधिक इस्तेमाल से यही खतरा बच्चों व नौजवानों को होगा। उनकी दिमागी क्षमता का उस तरह विकास नहीं हो सकेगा, जितनी अपेक्षा की जाती है। इसीलिए, अगर एआई को 'ड्रग्स' बताया जा रहा है, तो गलत नहीं है। यह एक तरह की लत है, जो यदि हमारे बच्चों को लग गई, तो वे इसके गुलाम हो जाएंगे। क्या हम अपना भविष्य यूं बर्बाद करना चाहते हैं? अगर नहीं, तो हमें एआई से दूरी बनानी ही होगी।

दीपक कुमार, टिप्पणीकार

Hindustan Page No-10

चंद्रयान-4 मिशन चंद्रमा से नमूने लेकर आएगा, 2028 में प्रक्षेपण

- इसरो प्रमुख बोले- इस वित्तीय वर्ष में सात अन्य प्रक्षेपणों की योजना
- कहा,भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान 2027 में ही है निर्धारित

कोलकाता, प्रेट्र : भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष वी. नारायणन ने कहा कि चंद्रयान-4 का प्रक्षेपण वर्ष 2028 में होगा, जबकि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान साल 2027 में ही निर्धारित है। चंद्रयान-4 चंद्रमा से नमूने वापस लाने का प्रयास करेगा और यह भारत का अब तक का सबसे जटिल चंद्र अभियान होगा। वर्तमान में केवल अमेरिका, रूस और चीन ने ही ऐसी क्षमता का प्रदर्शन किया है। इस वित्तीय वर्ष में सात अन्य प्रक्षेपणों की योजना के साथ इसरो विज्ञान, प्रौद्योगिकी और उद्योग क्षमता में तेजी से विस्तार के चरण की तैयारी कर रहा है।

एक साक्षात्कार में नारायणन ने कहा कि इसरो चालू वित्तीय वर्ष के अंत से पहले सात और प्रक्षेपणों का लक्ष्य बना रहा है, जिसमें एक वाणिज्यिक संचार उपग्रह और कई पीएसएलवी तथा जीएसएलवी मिशन शामिल हैं। पूरी तरह से भारतीय उद्योग द्वारा निर्मित पहले पीएसएलवी का प्रक्षेपण एक मील का पत्थर होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने चंद्रयान-4 मिशन को मंजूरी दे दी है और हम इसके लिए 2028 का ही लक्ष्य रख रहे हैं।''

कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेते इसरो के अध्यक्ष वी. नारायणन ● प्रेट्र

एक अन्य प्रमुख मिशन लूपेक्स है जिसका उद्देश्य जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (जाक्सा) के साथ चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी से बने बर्फ का अध्ययन करना है। नारायणन ने कहा कि मिशन की बढ़ती मांग के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए इसरो अगले तीन वर्षों में अपने वार्षिक अंतरिक्ष यान उत्पादन को तिगुना करने पर भी काम कर रहा है। इसरो ने एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन पर काम शुरू कर दिया है, जिसे 2035 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

Dainik Jagaran Page No-11

गौरैया की घटती संख्या चिंताजनक संरक्षण के लिए जनचेतना बढ़ाएं

जागरण संवाददाता, पटना : गौरैया संरक्षण को लेकर रविवार को कलमगार फाउंडेशन की ओर से एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम एलईएएफ का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम संजीवनी आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य तेजी से घटती गौरैया की संख्या पर चिंता व्यक्त करना और उसके संरक्षण को लेकर समाज में जनचेतना बढ़ाना था। इस मौके पर विशेषज्ञों ने बताया कि शहरीकरण, मोबाइल टावरों की बढ़ती संख्या, प्राकृतिक आवासों का नुकसान और प्रदूषण गौरैया की संख्या में लगातार गिरावट के प्रमुख कारण हैं। उन्होंने घरों में छोटे-छोटे घोंसलों की व्यवस्था, जल और दाना उपलब्ध कराने के साथ ही पेड़-पौधों को बचाने जैसी प्रभावी पहल की आवश्यकता पर जोर दिया। वहीं कलमगार फाउंडेशन के प्रतिनिधियों ने कहा कि गौरैया केवल एक पक्षी नहीं बल्कि हमारे पर्यावरण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसके संरक्षण से जैव विविधता को मजबूत किया जा सकता है। कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत संबोधन से हुआ। कार्यक्रम में प्रकृति से जुड़ी शायरी, गजल, कविताओं की प्रस्तुति कलाकार कुंदन क्रांति, सलमान सिद्दीकी, अमृतेश मिश्रा, अनिकेत पाठक, दीपक कुमार पंकज, अमर सिंह, पूजा भूषण झा, सुजीत, अर्जुन ने दिया। जिसने श्रोताओं को प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में यूएनडीपी के अधिकारी कुमार दीपक ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोगों को जागरूक किया। संजीवनी आई हॉस्पिटल के डॉ. सुनील ने कलमगार फाउंडेशन के प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण हर नागरिक की जिम्मेदारी है।

Dainik Jagaran Page No-6

राष्ट्रपति व राज्यपाल के लिए विधेयकों को मंजूरी की समयसीमा पर इसी सप्ताह फैसला संभव

माला दीक्षित, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए विधेयकों पर मंजूरी की समयसीमा तय करने पर इसी सप्ताह फैसला सुना सकती है। पीठ की अगुआई करने वाले प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई 23 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ऐसे में उनके सेवानिवृत्त होने से पहले फैसला आएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंशियल रिफरेंस भेजकर 14 कानूनी सवालों पर कोर्ट से राय मांगी है। इनमें मुख्य रूप से यही पूछा गया है कि जब संविधान में विधेयकों पर मंजूरी को लेकर राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए कोई समयसीमा तय नहीं है तो क्या कोर्ट उनके लिए समयसीमा तय कर सकता है। इस मामले में कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, उसका पूरे देश और सभी राज्यों पर व्यापक प्रभाव होगा।

प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की संविधान पीठ ने दस दिनों तक लंबी सुनवाई करके 11 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अगर किसी कारणवश फैसला नहीं सुनाया जाता है और पीठ का कोई न्यायाधीश

- संविधान पीठ की अगुआई करने वाले सीजेआइ गवई 23 नवंबर को हो रहे सेवानिवृत्त
- राष्ट्रपति ने प्रेसिडेंशियल रिफरेंस भेजकर 14 कानूनी सवालों पर मांगी है कोर्ट से राय

सेवानिवृत्त हो जाता है तो नियमानुसार पूरे मामले पर नए सिरे से नई पीठ सुनवाई करती है। ऐसे में हमेशा यही होता है कि अगर किसी मामले में सुनवाई करके फैसला सुरक्षित रखा गया है तो पीठ के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति से पहले फैसला आ जाता है। इसलिए इस मामले में 23 नवंबर से पहले फैसला आने की पूरी संभावना है।

राष्ट्रपति और राज्यपालों के विधेयकों पर मंजूरी की समयसीमा को लेकर मुद्दा तब उठा था, जब सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने गत अप्रैल में तमिलनाडु के मामले में फैसला दिया था जिसमें राज्य विधानसभा से पारित विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए समयसीमा तय कर दी गई थी। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल द्वारा रोके रखे गए तमिलनाडु के दस विधेयकों को मंजूर घोषित भी कर दिया था। यह पहला मौका था जब सीधे कोर्ट के आदेश से विधेयकों को मंजूरी मिली थी। इस फैसले के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने रिफरेंस भेजकर 14 कानूनी सवालों पर कोर्ट की राय मांगी है। राष्ट्रपति ने पूछा है कि जब संविधान में विधेयकों पर निर्णय लेने के संबंध में राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए कोई समयसीमा तय नहीं है तो क्या सुप्रीम कोर्ट समयसीमा तय कर सकता है। हालांकि रिफरेंस में सीधे तौर पर तमिलनाडु के फैसले को चुनौती नहीं दी गई है, लेकिन जो सवाल पूछे गए हैं वे सभी उस फैसले के इर्द-गिर्द ही घूमते हैं। रिफरेंस में पूछे गए सवाल अनुच्छेद-200 और 201 के तहत राज्य विधानसभा से पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति एवं राज्यपालों के निर्णय लेने की शक्तियों से संबंधित हैं। केंद्र सरकार और भाजपा शासित राज्यों ने रिफरेंस के पक्ष में बहस की यानी राष्ट्रपति एवं राज्यपालों के लिए कोर्ट द्वारा समयसीमा तय किए जाने का विरोध किया, जबकि गैर-भाजपा शासित राज्यों तमिलनाडु, केरल, बंगाल और हिमाचल प्रदेश ने रिफरेंस का विरोध किया और कहा कि राज्यपाल अनिश्चितकाल तक विधेयक नहीं रोक सकते।

****

Dainik Jagaran Page No-9

रमेश सिप्पी को आइकन आफ इंडियन सिनेमा व प्रियदर्शन को मिला जागरण अचीवर्स अवार्ड

एंटरटेनमेंट ब्यूरो, मुंबई: 'मेरी फिल्मों ने मेरे लिए बोला है। क्योंकि मैंने हमेशा महसूस किया है कि फोटोग्राफी हो, सेट हो, कलाकार हो या परफार्मेंस, हर विभाग में फिल्म को स्वयं बोलना चाहिए। निर्देशक बिना इन सभी लोगों का साथ मिले अच्छा काम नहीं कर सकता। यह अवार्ड मुझे सबके योगदान से मिला है।' यह कहना है इस वर्ष 50 वर्ष पूरे करने वाली फिल्म शोले के निर्देशक रमेश सिप्पी का, जिन्हें रविवार रात जागरण फिल्म फेस्टिवल (जेएफएफ) अवार्ड समारोह में आइकन आफ इंडियन सिनेमा से सम्मानित किया गया। प्रियदर्शन को जागरण अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। देशभर के आठ प्रदेशों और 14 शहरों में 74 दिनों तक चलने के बाद देश का एकमात्र घुमंतू फिल्म फेस्टिवल 'जागरण फिल्म फेस्टिवल' (जेएफएफ) का समापन रविवार रात मुंबई में जागरण अवाड्र्स के साथ हुआ।

मुंबई के एक पांच सितारा होटल में आयोजित समारोह में रमेश सिप्पी को फिल्मकार सुधीर मिश्रा, खुशबू सुंदर, किरण शांताराम और जागरण प्रकाशन लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बसंत राठौड़ ने सम्मानित किया। प्रियदर्शन ने मंच से रमेश सिप्पी को अपना गुरु बताया और कहा, 'मुझे बचपन से सिनेमा से प्यार रहा है। मैं हमेशा सोचता था कि हमारा सिनेमा वैश्विक स्तर तक विकसित क्यों नहीं हो रहा है। रमेश सिप्पी ने दुनिया को दिखाया कि हम भी उतने ही बेहतर हैं, जितने की वे। बचपन में मुझे क्रिकेट का शौक था, लेकिन एक

JAGRAN FILM FESTIVAL

- जागरण फिल्म फेस्टिवल का हुआ समापन, फुले ने जमाई धाक
- आठ प्रदेशों और 14 शहरों में 74 दिनों तक चला जेएफएफ

मुंबई के पांच सितारा होटल में रविवार को जागरण फिल्म फेस्टिवल के अवार्ड समारोह में रमेश सिप्पी को पुरस्कार प्रदान करते सुधीर मिश्रा (बाएं) और किरण शांताराम (दाएं) ● जागरण

दुर्घटना में मेरी बाईं आंख को नुकसान पहुंचा था। मेरे पिता लाइब्रेरियन हुआ करते थे। उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, इसी वजह से आज मैं यहां खड़ा हूं। आज भी टाम एंड जेरी कार्टून देखता हूं। वह मेरी पसंदीदा फिल्म है।'18 नवंबर को फिल्मकार वी. शांताराम की 125वीं जयंती से पूर्व उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान उनके पुत्र किरण शांताराम ने कहा कि इस वर्ष अपने पिता के जीवन पर बनाई अपनी डाक्यूमेंट्री भी प्रदर्शित करेंगे। फिल्म फुले के लिए अभिनेत्री पत्रलेखा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया। पत्रलेखा हाल ही में मां बनी हैं, तो उनकी जगह अवार्ड लेने पहुंचे उनके पति और अभिनेता राजकुमार राव ने कहा, उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिलते, लेकिन जितने मिलते है, उसमें उन्होंने खुद को साबित किया है। अभिनेता विनीत कुमार सिंह को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता व्यूवर्स च्वाइस का अवार्ड मिला। विनीत ने कहा, 'ये व्यूवर्स च्वाइस अवार्ड है तो मैं इसे दर्शकों को ही समर्पित करना चाहूंगा। नया-नया पिता बना हूं। संयोग की बात विक्की भी पिता बना है।

अवार्ड सूची

- **आइकन आफ इंडियन सिनेमा :** रमेश सिप्पी
- **जागरण अचीवर्स अवार्ड :** प्रियदर्शन
- **सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ओटीटी :** जयदीप अहलावत (पाताल लोक सीजन-2)
- **सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ओटीटी :** सबा आजाद (सांग्स आफ पैराडाइज)
- **सर्वश्रेष्ठ अभिनेता :** प्रतीक गांधी (फुले)
- **सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री :** पत्रलेखा (फुले)
- **सर्वश्रेष्ठ स्क्रीनप्ले :** कार्तिक राधाकृष्णन (एन आर्डर फ्राम स्काई)
- **सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी :** सुनीता राडिया (फुले)
- **सर्वश्रेष्ठ एडिटिंग :** स्वरूप रघु और अरण्य सहाय (ह्यूमन्स इन द लूप)
- **सर्वश्रेष्ठ बैकग्राउंड स्कोर :** एआर रहमान (छावा)
- **सर्वश्रेष्ठ म्यूजिक डायरेक्टर :** शांतनु घटक (मंगला)
- **सर्वश्रेष्ठ शार्ट फिल्म इंटरनेशनल :** देअर विल कम शार्ट रेन्स (एलहम अहसास)
- **सर्वश्रेष्ठ शार्ट फिल्म भारतीय :** रोजेज आर (दिग्विजय अंधोरिकर)
- **जेएफएफ अनटाइटल्ड :** शिव एंड टीम
- **फीप्रेस्की इंडिया राष्ट्रीय :** तन्वी द ग्रेट
- **फीप्रेस्की इंडिया स्पेशल मेंशन :** मोग असुम
- **सर्वश्रेष्ठ ओटीटी फिल्म :** सांग्स आफ पैराडाइज (दानिश रेंजू)
- **सर्वश्रेष्ठ डाक्यूमेंट्री :** घोस्ट नेट्स
- **सर्वश्रेष्ठ डेब्यू डायरेक्टर :** रुमाना मोल्ला (मिनिमम)
- **सर्वश्रेष्ठ निर्देशक :** अरण्य सहाय (ह्यूमन्स इन द लूप)
- **फेस्टिवल में सबसे ज्यादा प्रशंसित फिल्म** (आडियंस च्वाइस) : पुतुल
- **सर्वश्रेष्ठ इंडियन फिल्म :** ह्यूमन्स इन द लूप
- **सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओटीटी :** सांग्स आफ पैराडाइज
- **सर्वश्रेष्ठ ओटीटी सीरीज :** पाताल लोक-2

Dainik Jagaran Page No-9

भारत ने अक्टूबर के दौरान रूस से 2.5 अरब यूरो का कच्चा तेल खरीदा

- रूसी कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाए जाने से पहले दूसरा सबसे बड़ा खरीदार रहा भारत
- भारत की कुल खरीद में कच्चे तेल का योगदान 81 प्रतिशत, उसके बाद कोयले का 11%

नई दिल्ली, प्रेट्र: रूसी कच्चे तेल के दूसरे सबसे बड़े खरीदार भारत ने रूसी कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाए जाने से पहले अक्टूबर में रूस से कच्चे तेल की खरीद पर 2.5 अरब यूरो तक खर्च किए हैं। सितंबर में भी 2.5 अरब यूरो का कच्चा तेल खरीदा गया था। अक्टूबर में भारत के रूसी कच्चे तेल के आयात में माह-दर-माह आधार पर 11 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इस दौरान जहां निजी रिफाइनरियों का आयात भारत के कुल आयात का दो-तिहाई से अधिक था, वहीं सरकारी रिफाइनरियों ने अक्टूबर में मासिक आधार पर अपने रूसी आयात की मात्रा दोगुनी कर दी।

सेंटर फार रिसर्च आन एनर्जी एंड क्लीन एयर (सीआरईए) के अनुसार, अक्टूबर में चीन के बाद भारत रूसी जीवाश्म ईंधन का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बना रहा। 22 अक्टूबर को अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध के वित्तपोषण को हतोत्साहित करने के लिए रूस की दो सबसे बड़े तेल उत्पादक कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकआयल पर प्रतिबंध लगा दिया था। इन प्रतिबंधों के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचपीसीएल-मित्तल एनर्जी लिमिटेड और मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड जैसी कंपनियों ने फिलहाल रूसी तेल का आयात रोक दिया है। रूस ने अक्टूबर में छह करोड़ बैरल कच्चा तेल दूसरे देशों को भेजा है। भारत की कुल खरीद में कच्चे तेल का योगदान 81 प्रतिशत (2.5 अरब यूरो) रहा, उसके बाद कोयले का 11 प्रतिशत (35.1 करोड़ यूरो) और तेल उत्पादों का सात प्रतिशत (22.2 करोड़ यूरो) रहा है।

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

Dainik Jagaran Page No-9

2030 तक एक ट्रिलियन डालर का हो जाएगा खुदरा बाजार

नई दिल्ली, एएनआइः खर्च करने योग्य आय बढ़ने और तेजी से डिजिटलीकरण अपनाने और व्यापक होते आकांक्षी वर्ग के चलते भारत का खुदरा बाजार 2030 तक एक ट्रिलियन डालर का हो जाएगा। वेंचर कैपिटल फर्म, फायरसाइड वेंचर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह बदलाव केवल मात्रा के लिहाज से नहीं होगा बल्कि देश में खरीदारी के ढांचे में भी बदलाव देखने को मिलेगा।

रिपोर्ट के अनुसार, नए प्रारूपों और डिजिटल फर्स्ट को अपनाने से ब्रांडेड रिटेल का आकार 2030 तक दोगुना होकर 730 अरब डालर तक पहुंच जाएगा। यह देश के कुल खुदरा बाजार का लगभग आधा होगा। फायरसाइड इस बात पर प्रकाश डालता है कि डिजिटल ब्रांड पारंपरिक ब्रांड की तुलना में दो से तीन गुना तेजी से विस्तार कर रहे हैं। नए जमाने के ब्रांड डेटा आधारित उत्पाद नवाचार, बेहतर वितरण नेटवर्क और अच्छे ग्राहक

खर्च करने योग्य आय बढ़ने और तेजी से डिजिटलीकरण अपनाने से भारत के खुदरा बाजार को मिलेगा फायदा

जुड़ाव पर ज्यादा केंद्रित करते हैं और इसका उन्हें लाभ मिलता है। कंपनी का विश्लेषण उभरते उपभोक्ता समूहों के एक विशाल परिदृश्य को दर्शाता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2030 तक भारत में 110 करोड़ इंटरनेट यूजर और 40 करोड़ से ज्यादा आनलाइन खरीददार होने की उम्मीद है। फायरसाइड वेंचर्स का मानना है कि अगले सौ प्रतिष्ठित ब्रांड उन कंपनियों के होंगे, जो नियमों को फिर से लिख रहे हैं।

दूसरी छमाही में नरम रहेगी खाद्य महंगाई

- **सामान्य से अधिक मानसूनी बारिश और बेहतर बोआई का मिलेगा लाभ**
- **कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से ईंधन मुद्रास्फीति नकारात्मक क्षेत्र में रही**

नई दिल्ली, एएनआइः सामान्य से अधिक मानसूनी बारिश और बेहतर बोआई के चलते चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में खाद्य महंगाई के नरम रहने की उम्मीद है। हालांकि, एक प्रतिकूल आधार अगले वर्ष यानी 2027 में खाद्य मुद्रास्फीति को बढ़ा सकता है। आधार प्रभाव से तात्पर्य इस बात से है कि पिछले वर्ष की समान अवधि में कीमतों के असामान्य रूप से उच्च या निम्न रहने पर इस वर्ष की मुद्रास्फीति कैसे अधिक या कम दिखाई देती है।

आइसीआइसीआइ बैंक के वैश्विक बाजार क्षेत्रीय अपडेट के अनुसार, 'टमाटर, प्याज और चुनिंदा अनाज जैसी कई उच्च आवृत्ति वाली वस्तुओं में सुधार से इस वर्ष थोक खाद्य महंगाई में उल्लेखनीय कमी आई है।' ईंधन मुद्रास्फीति नकारात्मक क्षेत्र में रही, जिसे पिछले वर्ष की तुलना में वैश्विक कच्चे तेल की कम कीमतों का समर्थन प्राप्त था।

धातुओं और कई औद्योगिक इनपुटों में कीमतों के दबाव में कमी को दर्शाते हुए, मैन्यूफैक्चरिंग उत्पादों की मुद्रास्फीति में भी कमी आई। हालांकि, आभूषण, तंबाकू, फार्मास्यूटिकल्स और चुनिंदा गढ़ी हुई धातुओं सहित कुछ श्रेणियों में क्रमिक मजबूती देखी गई, जिससे संकेत मिलता है कि वैश्विक कमोडिटी कीमतों में उतार-चढ़ाव आगे कुछ ऊपर की ओर दबाव बढ़ा सकता है।

Dainik Jagaran Page No-9

कई राज्यों में बनाए जाएंगे परमाणु ऊर्जा संयंत्र

गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश में जमीन का मूल्यांकन कर रही सरकारी कंपनी एनटीपीसी

नई दिल्ली, प्रेट्र: सरकारी स्वामित्व वाली बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी देश के विभिन्न स्थानों पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रही है। यह ऊर्जा संयंत्र 700 मेगावाट, 1,000 मेगावाट और 1,600 मेगावाट के होंगे। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एनटीपीसी का लक्ष्य 2047 तक भारत की प्रस्तावित 100 गीगावाट परमाणु क्षमता में 30 प्रतिशत हिस्सेदारी (30 गीगावाट) हासिल करना है। उद्योग का अनुमान बताता है कि एक गीगावाट क्षमता वाले परमाणु संयंत्र के लिए 15,000-20,000 करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता होती है और आमतौर पर अवधारणा से लेकर चालू होने तक कम से कम तीन साल लगते हैं।

कंपनी की परमाणु विस्तार योजनाओं पर बात करते हुए अधिकारी ने कहा कि एनटीपीसी वर्तमान में गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों में भूमि विकल्पों का मूल्यांकन कर रही है। कंपनी की रणनीतिक योजना में शामिल अधिकारी ने कहा, "परमाणु परियोजनाओं की क्षमता 700 मेगावाट, 1,000 मेगावाट और 1,600 मेगावाट होगी।" एनटीपीसी परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) द्वारा चिन्हित और अनुमोदित राज्यों में परमाणु ऊर्जा विकास कार्य जारी रखेगी। अधिकारी ने कहा, "एईआरबी संयंत्र लगाने के स्थान को मंजूरी देगा और इसके बाद कंपनी परियोजनाओं को क्रियान्वित करेगी।"

विदेश में यूरेनियम भंडारों के अधिग्रहण की संभावना तलाश रही एनटीपीसी

कंपनी ने परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए जरूरी कच्चे माल की उपलब्धता को लेकर भी प्रयास शुरू कर दिए हैं। उसने विदेश में यूरेनियम परिसंपत्तियों के अधिग्रहण की संभावना तलाश रही है। यूरेनियम परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त होने वाला प्राथमिक ईंधन है। एनटीपीसी ने विदेश में यूरेनियम परिसंपत्तियों की तकनीकी जांच-पड़ताल के लिए यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआइएल) के साथ एक मसौदा समझौते पर पहले ही हस्ताक्षर कर दिए हैं।

नए ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाई कंपनी

एनटीपीसी नए ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाई है। एनटीपीसी की वेबसाइट के अनुसार, कंपनी की वर्तमान में समूह स्तर पर 84,848 मेगावाट की स्थापित क्षमता है, जिसमें कोयला, गैस, तरल ईंधन, जलविद्युत और सौर ऊर्जा शामिल हैं। वर्तमान में, एनटीपीसी राजस्थान में लगभग 42,000 करोड़ रुपये के निवेश से भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड (एनपीसीआइएल) के साथ एक संयुक्त उद्यम (जेवी) में एक परमाणु परियोजना स्थापित कर रही है। एनटीपीसी की अश्विनी (अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड) में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि एनपीसीआइएल के पास 51 प्रतिशत की बहुलांश हिस्सेदारी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सितंबर में बांसवाड़ा में अश्विनी द्वारा स्थापित की जा रही 4X700 मेगावाट की माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी थी।

- कंपनी का लक्ष्य 2047 तक भारत की प्रस्तावित 100 गीगावाट परमाणु क्षमता में 30 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करना
- यह ऊर्जा संयंत्र 700 मेगावाट, 1,000 मेगावाट और 1,600 मेगावाट के होंगे, एईआरबी देगा स्थान को मंजूरी

1,600 मेगावाट संयंत्र के लिए तकनीकी सहयोग पर विचार

तकनीक के मोर्चे पर बात करें तो एनटीपीसी 700 मेगावाट और 1,000 मेगावाट के संयंत्रों के देश में ही विकसित प्रेसराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर) का उपयोग करने पर विचार कर रही है। हालांकि, कंपनी 1,600 मेगावाट की परमाणु परियोजनाओं के लिए तकनीकी सहयोग पर विचार कर सकती है।

Dainik Jagaran Page No-9

वीरपुर, मुजफ्फरपुर, सहरसा और वाल्मीकि नगर में छोटे एयरपोर्ट बनाये जाएंगे

सुविधा: रक्सौल में बनेगा राज्य का आठवां सबसे बड़ा एयरपोर्ट

Hindustan Page No-8

Useful For Mains

'जलवायु-उत्तरदायी दृष्टिकोण के साथ प्रगति का पथ तैयार कर रहा है भारत'

नई दिल्ली, प्रेट : संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के कार्यवाहक प्रशासक एवं संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव हाओलियांग शू ने कहा है कि भारत ने यह प्रदर्शित किया है कि आर्थिक विकास और सामाजिक समावेशन एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। वह अपनी सफलता की कहानियों को एक अधिक समतापूर्ण विश्व के लिए वैश्विक सबक में बदलने में मदद कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की विकास गाथा केवल आर्थिक प्रगति के बारे में नहीं है, बल्कि प्रौद्योगिकी और सहभागी शासन के उपयोग के बारे में भी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकास के उद्देश्य प्राप्त हों और इसके लाभ से कोई भी वंचित न रहे।

एक साक्षात्कार में हाओलियांग शू ने कहा कि जलवायु अनुकूलन, नवीकरणीय ऊर्जा और समावेशी डिजिटल वित्त के प्रति भारत की प्रतिबद्धता, विकास और स्थिरता के बीच संतुलन बनाने का एक खाका प्रस्तुत करती है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसा "विकास पथ" तैयार कर रहा है जो आर्थिक रूप से सुदृढ़ और जलवायु-उत्तरदायी दोनों हों। हाओलियांग शू डिजिटल परिवर्तन और जलवायु कार्रवाई सहित सहयोग के नए क्षेत्रों को मजबूत करने और उनकी पहचान करने के लिए तीन दिवसीय भारत यात्रा पर आए थे। वैश्विक चुनौतियों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि यूएनडीपी के नवीनतम मानव विकास सूचकांक से पता चलता है कि मानव विकास में वैश्विक प्रगति 35 वर्षों के निचले स्तर पर आ गई है और पिछले दो वर्षों से यह लगभग स्थिर है। साथ ही, उन्होंने जलवायु परिवर्तन और गरीबी सहित विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए भारत के विकास माडल की सराहना की। उन्होंने कहा, "हम विकास के उद्देश्यों, सभी स्रोतों से विकास वित्तपोषण और जवाबदेह एवं समावेशी संस्थागत क्षमता को और भी बेहतर ढंग से प्रभावी करने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। उन्होंने विशेष रूप से भारत के प्रमुख कार्यक्रमों जैसे मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) और आयुष्मान भारत का उल्लेख किया और कहा कि ये कार्यक्रम आजीविका सुरक्षा को सामाजिक सुरक्षा के साथ जोड़ते हैं।

- **यूएनडीपी के शीर्ष अधिकारी ने कहा- भारत की विकास गाथा केवल आर्थिक प्रगति के बारे में नहीं**
- **बोले- जलवायु अनुकूलन, नवीकरणीय ऊर्जा और समावेशी डिजिटल वित्त के प्रति भारत प्रतिबद्ध**

Dainik Jagaran Page No-8

सूरत में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को निर्माणाधीन मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का माडल दिखाता एक अधिकारी। प्रेट

बुलेट ट्रेन परियोजना के अभियंता अपने अनुभवों का करें दस्तावेजीकरण : मोदी

नई दिल्ली, प्रेट : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना पर काम कर रहे अभियंताओं से कहा है कि वे अपने अनुभवों का दस्तावेजीकरण करें। यह इस तरह की किसी दूसरी परियोजना की योजना बनाने और उसके क्रियान्वयन में काम आएगा। वह शनिवार को सूरत में मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे (एमएचएसआर) परियोजना के अभियंताओं और अन्य श्रमिकों के साथ बातचीत कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि यदि परियोजना से प्राप्त अनुभवों को एक 'ब्ल्यू बुक' की तरह दर्ज और संकलित किया जाए तो देश बुलेट ट्रेन के बड़े पैमाने पर क्रियान्वयन की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ सकता है। भारत को बार-बार प्रयोग करने से बचना चाहिए। इसके बजाय मौजूदा माडल से सीखी गई बातों को अमल में लाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि इस तरह के रिकार्ड रखने से भविष्य में छात्रों को लाभ होगा और राष्ट्र निर्माण में योगदान मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि हम अपना जीवन यहीं समर्पित करेंगे और देश के लिए कुछ मूल्यवान छोड़ जाएंगे। उन्होंने परियोजना की प्रगति के बारे में जानकारी ली, जिसमें गति और समय-सारिणी के लक्ष्यों का पालन भी शामिल था। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि श्रमिकों ने उन्हें आश्वासन दिया कि परियोजना बिना किसी कठिनाई के सुचारू रूप से आगे बढ़ रही है। केरल की एक इंजीनियर ने गुजरात के नवसारी स्थित नाइज बैरियर फैक्ट्री में काम करने का अपना अनुभव साझा किया, जहां सरिया की वेल्डिंग के लिए रोबोटिक इकाइयों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

- **प्रधानमंत्री ने कहा, यह इस तरह की किसी दूसरी परियोजना की योजना बनाने व उसके क्रियान्वयन में आएगा काम**

Dainik Jagaran Page No-8

भाषा विमर्श

डा.बुद्धिनाथ मिश्र
देहरादून, उत्तराखंड

खतरे शुद्धतावादी दुराग्रहों के!

हिंदी भाषा निरंतर प्रवाहमय और परिवर्तनशील है। इसमें शुद्धतावादी आग्रह इसके नैसर्गिक विकास को बाधित करता है...

भाषा के संबंध में लोकभाषा के दो महान कवियों ने जो टिप्पणी की है, वह अलग-अलग मंतव्य की होते हुए भी हमें सोचने की पृथक दिशा देती है। कबीर का समाज तत्सम का नहीं, तद्भव का समाज था। संस्कृत उनके लिए कूप-जल थी (संस्कीरत है कूपजल)। वे काशी के थे, जहां ज्ञानवापी (विद्या का कुआं) की केंद्रीय भूमिका थी। काशी प्राचीन काल से 'सर्वविद्या की राजधानी' थी, जिसकी माध्यम-भाषा संस्कृत थी। ज्ञान-विज्ञान के गंभीर विषयों को वहन करने का भार वृहत्तर भारत की मानक भाषा संस्कृत ही उठा सकती थी। सामान्य जन के संवाद के लिए लोकभाषा थी, जो कभी प्राकृत, कभी पाली, कभी अपभ्रंश तो कभी ब्रज, अवधी, मैथिली जैसी सशक्त लोकभाषाएं थीं। कबीर ने इन्हीं के लिए 'भाषा बहता नीर' कहा है। बहते हुए पानी के लिए उर्दू में बड़ा अच्छा शब्द है- आबेरवां। बनारसी शायर नजीर बनारसी ने गंगाजी पर लिखी कविता में कहा है- 'पहनके आबेरवां की साड़ी, रवां है सीमाबवार गंगा'। बहते पानी में नवीनता को ग्रहण करने की अपार क्षमता होती है और सड़न की गुंजाइश भी कम रहती है।

दूसरी ओर, शास्त्रीय भाषा के पुरोधा गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं-'भाषा भनिति भूति भलि सोई। सुरसरि सम सबकहं हित होई।' वे भाषा और कविता को गंगाजी की भांति पवित्र और हितकर देखना चाहते हैं। यद्यपि वामपंथियों ने कबीर और तुलसी को दो विपरीत दिशाओं में चलते दिखाने का प्रयास किया है, लेकिन यदि ध्यान से देखें तो दोनों अपने-अपने ढंग से लोकभाषा में गहन शास्त्रीय विमर्श को उतार रहे थे। दोनों ने अपनी अभिव्यक्ति को धारदार बनाने के लिए लोकभाषा के खांचे में तत्सम शब्दों को बैठाने हेतु उनकी भरपूर घिसाई भी की और अरबी-फारसी के प्रचलित शब्दों को मुक्त भाव से अपनाया भी।

आज की हिंदी (खड़ी बोली) ब्रज या अवधी की तरह केवल साहित्यिक भाषा नहीं है, वह एक साथ प्रशासन, बैंकिंग, विज्ञान और चिकित्सा की भाषा भी होती जा रही है। अपनी वृहत्तर भूमिका को निभाने के लिए इसे संस्कृत से विरासत में मिले विशाल शब्द-भंडार का उपयोग तो करना है ही, विश्व की अन्य भाषाओं से भी शब्द उधार लेने पड़ते हैं। विज्ञान-प्रौद्योगिकी के शब्दों के लिए तो हमारी राष्ट्रीय नीति है कि हम वैश्विक स्तर पर प्रचलित शब्दों का ही प्रयोग करें। कंप्यूटर, माउस, चेक, बैंक आदि के लिए, पर्यायवाची शब्द बनाए गए थे, मगर वे चलन में नहीं आ सके। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि भाषा का प्रयोग समाज करता है। इसलिए, शब्दों को स्वीकारने या नकारने का पहला और अंतिम निर्णय समाज ही करेगा। कुछ शुद्धतावादी विद्वान इन दिनों हिंदी में प्रचलित अंग्रेजी, फारसी, अरबी शब्दों को हटाने और उनकी जगह संस्कृत के अपरिचित शब्दों को लाने में सक्रिय दिखते हैं। उन्हें याद रखना होगा कि भाषा अनावश्यक शब्दों को स्वयं बाहर निकाल देगी और आवश्यक शब्दों को अपना लेगी। इसलिए, शुद्धतावादी दुराग्रह हिंदी के नैसर्गिक विकास को बाधित करेगा।

buddhinathji@gmail.com

Dainik Jagaran Page No-18

परिचर्चा

हिंदी साहित्य का बदला परिदृश्य

कुछ समय पहले तक कहा जा रहा था कि हिंदी साहित्य में न सिर्फ पाठकीयता घटी है, बल्कि प्रकाशक हिंदी लेखकों को उचित रायल्टी नहीं देते हैं। लेकिन विनोद कुमार शुक्ल की पुस्तक की बिक्री और उनको प्रकाशक द्वारा दी जाने वाली रायल्टी की चर्चा के बाद यह भी कहा जाने लगा है कि हिंदी साहित्य के अच्छे दिन आ गए हैं। हिंदी साहित्य के इस बदले हुए परिदृश्य पर वरिष्ठ कथाकार अजगर वजाहत और युवा रचनाकार भगवंत अनमोल की प्रतिक्रिया...

बदलाव को समझने की आवश्यकता

असगर वजाहत
नोएडा, उत्तर प्रदेश

जब तक मध्यम वर्गीय हिंदीभाषी हिंदी साहित्य पढ़ता हुआ नहीं दिखेगा, तब तक साहित्य के अच्छे दिन नहीं आ सकते। मध्यम वर्ग के लोग हिंदी पढ़ते नजर नहीं आते। हिंदी माध्यम स्कूल ना के बराबर हैं, जब हिंदी पढ़ाई नहीं जा रही है तो हिंदी का पाठक कहां से आएगा। लेकिन यदि लोग कह रहे हैं कि हिंदी साहित्य के परिदृश्य में सकारात्मक बदलाव आया है, तो थोड़ा आश्चर्य होता है। क्योंकि यदि इसका आधार यह है कि किसी प्रकाशक ने किसी लेखक की कृतियों की बिक्री कर ली या उसने लेखक को लाखों की रायल्टी दे दी, तो यह तो अप्रत्याशित बात हुई। साल भर पहले तक लेखकों को यह शिकायत थी कि प्रकाशक पैसा नहीं देते। अचानक एक प्रकाशक ने लेखक को 30 लाख रुपये दे दिए, यह अप्रत्याशित बात हुई। वैसे तो लेखक को पैसा मिल रहा है, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे जो समझ में न आने वाली बात है, वह स्पष्ट हो जाती तो बात और अच्छी थी।

दूसरी बात यह है कि कुछ महीने पहले हंस में अशोक वाजपेयी का लेख छपा था, जिसमें उन्होंने साफ लिखा था कि हिंदीभाषियों ने हिंदी साहित्य को अपने जीवन में वह स्थान नहीं दिया है, जो दिया जाना चाहिए था। अशोक वाजपेयी ने कठोर शब्दों का प्रयोग किया था। एक ओर तो हम यह शिकायत करते हैं कि हिंदी में पाठक नहीं हैं, दूसरी तरफ यह कह रहे हैं कि हिंदी की किताबें धड़ाधड़ बिक रही हैं और लाखों रुपये आ रहे हैं। दोनों में जो विरोधाभास है, उसे समझने की जरूरत है। एक ही प्रकाशक करोड़ों कमा रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता। दूसरे प्रकाशकों ने कभी नहीं कहा कि हमारी किताबों की बिक्री लाखों प्रतियों तक पहुंच गई है।

दूसरी बात यह है कि पैसे से लेखक की महानता नहीं सिद्ध होती। मान लीजिए कि विनोद कुमार शुक्ल की किताबें यदि न बिकें और उनको 30 लाख रुपये न मिलें, फिर भी वह बड़े लेखक ही कहलाएंगे। क्योंकि वह बड़े लेखक हैं। बड़ा लेखक होने के लिए व्यावसायिक शर्त अप्रत्यक्ष रूप से लगाना ठीक नहीं है। मान लीजिए कि मुझे 30 लाख की रायल्टी नहीं मिलती है, तो आप कह दें कि मैं घटिया लेखक हूं। इसलिए साहित्य के परिदृश्य को पैसे से और किताब की बिक्री से जोड़ने का कोई तुक नहीं है। एक समय जो घोस्ट राइटर थे, जासूसी आदि पल्प फिक्शन लिखते थे, इस तरह तो उनके हमेशा ही अच्छे दिन रहे।

जहां तक कंटेंट की बात है, पहले भी अच्छा साहित्य रचा जा रहा था और आज भी रचा जा रहा है। किसी भी लेखक की मृत्यु के 50 वर्षों के बाद उसका मूल्यांकन होता है। आधी शताब्दी तक जो लेखक पाठकों के बीच रहता है, वही अच्छा लेखक है। आज के लेखन में कमर्शियल दबाव आया है। यह कोई गलत बात नहीं है। जो बाजार की मांग पर लिखा जाता है, वह भी उस सीढ़ी का एक पाया है, जिस पर चढ़कर पाठक ऊपर पहुंचता है और वह गंभीर साहित्य भी पढ़ता है।

awajahat@yahoo.com

युवा लेखक और पाठक लाए परिवर्तन

भगवंत अनमोल
जालपुर, उत्तर प्रदेश

आज हिंदी साहित्य में अच्छे दिनों की आहट का श्रेय युवा लेखकों और युवा पाठकों को मिलना चाहिए। पिछली सदी के आखिरी दशक से यह धारणा बननी शुरू हो गई थी कि हिंदी किताबें कम बिकती हैं और पाठकों की साहित्य में रुचि घट रही है। वर्ष 2012 में जब मैं हिंदी लेखन से जुड़ा, तो एक दिलचस्प बात महसूस हुई। हिंदी में 'युवा लेखक' का अर्थ ठीक वैसे ही था, जैसे राजनीति में 'युवा नेता' का होता है। 40-50 वर्ष के प्रौढ़ को भी युवा लेखक कहा जाता है। एक बार मैंने प्रभात रंजन जी से पूछा कि हिंदी में अंग्रेजी की तरह 20-25 साल के लेखक क्यों नहीं दिखते? उस समय यह मात्र एक जिज्ञासा थी, लेकिन अब इसका जवाब सामने है। पिछले कुछ वर्षों में कई युवा चेहरे हिंदी लेखन में सक्रिय हुए हैं। परिणाम यही हुआ, जो चेतन भगत के आने से अंग्रेजी लेखन में देखने को मिला था। पांच हजार प्रतियों में बिककर 'बेस्टसेलर' कहलाने वाली अंग्रेजी की किताबों का दायरा लाखों तक पहुंच गया। हिंदी में भी यही बदलाव आया। नए लेखक अलग-अलग क्षेत्रों से नई ऊर्जा और नए पाठक लेकर आए। वे पाठक, जिन्होंने स्कूल के बाद शायद ही कोई हिंदी किताब पढ़ी हो। ये पाठक पारंपरिक हिंदी पाठक वर्ग से अलग थे। कहा भी जाता है कि जो लोग किसी नए क्षेत्र से आते हैं, उन्हें उसकी सीमाओं का अनुमान कम होता है। यह अनभिज्ञता लाभकारी होती है। जो शिकायत थी कि हिंदी पुस्तकों के पाठक कम हो गए हैं, वह साहित्यिक मठाधीशों तक ही सीमित रही। नए लेखकों और पाठकों ने तकनीक के सहारे अपने रास्ते स्वयं बनाए।

हिंदी पुस्तकों को इंटरनेट व तकनीक का सहारा मिला है। किसी पुस्तक पर रील बनती है, तो वह हजारों नए पाठकों तक पहुंचती है। जब किसी पुस्तक का नाम बार-बार सुनते हैं या उस पर बोलते देखते हैं, तो पाठकों में उसे पढ़ने की ललक पैदा होती है। अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी ई-कामर्स वेबसाइटों ने इसमें मदद की। अब एक क्लिक पर पुस्तकें पाठक के दरवाजे तक पहुंच रही हैं। परिणामस्वरूप हिंदी के पाठक बढ़े हैं। हालांकि परंपरागत पाठकों का घनत्व थोड़ा घटा है।

पहले एक विशेष विचारधारा का ही साहित्य में दबदबा रहा। दूसरे, जब तक कोई नया लेखक किसी बड़े नामवर की शरण में नहीं जाता था, तब तक हिंदी साहित्य में स्थापित नहीं हो सकता था। लेकिन युवा लेखकों ने किसी खास विचारधारा के मठाधीशों के शरण में जाने के बजाय सिर्फ पाठकों की रुचि के कंटेंट पर काम किया। परिणामतः आज कंटेंट बिक रहा है। विचारधाराओं की मठाधीशी समाप्त हो चुकी है। अब कंटेंट ही किंग है।

आज शहरों में होने वाले साहित्योत्सवों की भी पुस्तक संस्कृति के विकास में अहम भूमिका है। जागरण बेस्टसेलर सूची को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसने आम पाठकों को बताया कि देश में कौन-सी किताबें पढ़ी और खरीदी जा रही हैं। सामान्य पाठक इसे गंभीरता से लेते हैं। अतः हिंदी साहित्य के प्रति का रुझान कम हुआ है, इस धारणा पर पूर्णविराम भले न लगा हो, लेकिन अब अल्पविराम तो जरूर लग गया है।

bhagwantnovelwritter@gmail.com

Dainik Jagaran Page No-18

सरकारी स्कूलों के बच्चे खुद से निकालेंगे पत्रिका

पत्रिका तैयार करने में शिक्षक करेंगे सहयोग, महान विभूतियों की जीवनी पढ़ने के लिए किया जाएगा प्रेरित

जागरण संवाददाता, पटना: सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अब पत्रिका तैयार करेंगे और उसका संपादन भी स्वयं करेंगे। इस पहल में माध्यमिक विद्यालय के बच्चों को शामिल किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों में रचनात्मकता के माध्यम से किताबों की पढ़ने की आदत विकसित करना है। यह कार्यक्रम बच्चों में वैचारिक और तार्किक समझ को बढ़ाने के साथ-साथ किताबों के प्रति रुचि को भी प्रोत्साहित करेगा।

इस योजना के तहत विद्यार्थियों को किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय की ओर से एक पत्रिका तैयार की जाएगी, जिसका संपादन बच्चे स्वयं करेंगे, शिक्षकों के सहयोग से। शिक्षा विभाग का मानना है कि इससे बच्चों में लेखन की क्षमता और सृजनशीलता को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही, बच्चों को रचनात्मक बुक मार्ग बनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा और बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। शिक्षकों को भी बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए किताबों पर चर्चा करने, कहानियां लिखने और किताब पर आधारित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए कहा गया है।

साहित्य की किताबें कराई जाएंगी मुहैया

बच्चों द्वारा तैयार की गई पत्रिका को पुस्तकालय में रखा जाएगा। इसके साथ ही, जिले के सभी विद्यालयों में पुस्तकालयों को भी विकसित किया जाएगा। स्कूलों में बच्चों के पढ़ने के लिए पाठ्यक्रम के अलावा साहित्य और सामान्य ज्ञान की किताबें भी उपलब्ध कराई जाएंगी। पुस्तकालय में रखी जाने वाली किताबों में कहानी, देश के महान लोगों की जीवनी और प्रेरणादायी साहित्य भी शामिल होगा। स्कूली बच्चों द्वारा इन किताबों का सारांश विद्यालय की चेतना सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें सर्वाधिक किताबें पढ़ने वाले छात्र को प्रशंसा पत्र भी दिया जाएगा। इससे बच्चों में उत्साह बना रहेगा।

Dainik Jagaran Page No-17

व्यक्तिगत डाटा सुरक्षा का खाका तैयार, 200 करोड़ तक के जुर्माने का प्रविधान

- नागरिकों को मिलेगा व्यक्तिगत डाटा पर अधिक नियंत्रण
- कंपनियों पर डाटा संग्रह, उपयोग और सुरक्षा के कड़े मानक लागू

नई दिल्ली, प्रेट्र: भारत के डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) नियमों ने देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था में जवाबदेही, पारदर्शिता और यूजर्स के अधिकारों को मजबूत करने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश तय कर दिए हैं। इन नियमों का उद्देश्य नागरिकों को अपने व्यक्तिगत डेटा पर अधिक नियंत्रण देना है, जबकि कंपनियों के लिए डाटा संग्रह, उपयोग और सुरक्षा को लेकर कड़े मानक निर्धारित किए गए हैं। ये नियम बताते हैं कि कंपनियों को व्यक्तिगत डाटा कैसे एकत्र करना है, उसका प्रबंधन कैसे करना है और डाटा मालिक यानी 'डाटा प्रिंसिपल' के अधिकारों की रक्षा कैसे करनी है। वहीं 'डेटा फिड्यूशियरी' वे संस्थाएं हैं जो डाटा के उपयोग और उसकी प्रोसेसिंग का उद्देश्य तय करती हैं।

स्पष्ट सहमति और सरल भाषा में नोटिस आवश्यक: डीपीडीपी नियमों के अनुसार कंपनियों को यूजर्स से सहमति लेने से पहले स्पष्ट, सरल और समझने योग्य भाषा में नोटिस देना होगा। इस नोटिस में शामिल होना चाहिए कि कौन-सा डाटा लिया जा रहा है, किस उद्देश्य से प्रोसेस किया जाएगा, शिकायत का क्या तरीका होगा और सहमति वापस लेने की आसान प्रक्रिया क्या होगी। सहमति वापस लेने की प्रक्रिया उतनी ही आसान होनी चाहिए, जितनी आसानी से सहमति दी गई थी।

सहमति प्रबंधक की भूमिका और जवाबदेही: नियमों के तहत 'कंसेंट मैनेजर' वह प्लेटफार्म होगा जिसके माध्यम से यूजर्स अपने डाटा प्रोसेसिंग की सहमति को दे सकेंगे, प्रबंधित कर सकेंगे या सहमति वापस ले सकेंगे। नए नियम कंसेंट मैनेजर के पंजीकरण, जिम्मेदारियों, और निरीक्षण की प्रक्रिया स्पष्ट करते हैं। डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड जरूरत पड़ने पर इनके लाइसेंस को निलंबित या रद भी कर सकता है। कंपनियों को डाटा की सुरक्षा के लिए एन्क्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल, मानिटरिंग और लागिंग, बैकअप के सुरक्षा उपाय लागू करने होंगे।

डाटा उल्लंघन की स्थिति में प्रविधान : डाटा उल्लंघन की स्थिति में कंपनियों को प्रभावित उपयोगकर्ताओं को तुरंत स्पष्ट जानकारी देनी होगी कि उल्लंघन क्या है, संभावित जोखिम क्या हैं, और उन्हें क्या कदम उठाने चाहिए। साथ ही डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड को भी तुरंत सूचना देनी होगी, और 72 घंटे के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपनी होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि 200 करोड़ रुपये तक के भारी जुर्मानों के कारण कंपनियों को लगातार घटना प्रतिक्रिया प्रणाली तैयार करनी पड़ेगी।

डाटा मिटाने और संरक्षण की नई बाध्यताएं: दो करोड़ से ज्यादा यूजर्स वाले ई-कामर्स, 50 लाख से ज्यादा यूजर्स वाले आनलाइन गेमिंग और बड़े सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को तीन साल की यूजर निष्क्रियता के बाद डाटा मिटाना होगा, लेकिन मिटाने से 48 घंटे पहले यूजर को नोटिस भेजना अनिवार्य होगा। सभी कंपनियां डाटा प्रोसेसिंग की तारीख से कम से कम एक वर्ष तक रिकार्ड और लाग सुरक्षित रखेंगी।

बच्चों और दिव्यांगों के डाटा की अतिरिक्त सुरक्षा: बच्चों के डाटा प्रोसेसिंग के लिए अभिभावकों की सत्यापित सहमति अनिवार्य है। अभिभावक की पहचान विश्वसनीय पहचान प्रमाण या डिजिटल टोकन से सुनिश्चित करनी होगी। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी कुछ श्रेणियों को विशेष परिस्थितियों में आंशिक छूट मिलेगी। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अभिभावक सहमति के नियम भी परिभाषित किए गए हैं।

महत्वपूर्ण डाटा फिड्यूशियरी (एसडीएफ) के लिए कड़े आडिट: जिन कंपनियों को एसडीएफ वर्ग में रखा जाएगा उन्हें हर साल डाटा सुरक्षा असर आकलन और आडिट कराना होगा। एल्गोरिदम के जोखिम मूल्यांकन करने होंगे और यह सुनिश्चित करना होगा कि संवेदनशील डाटा भारत से बाहर न जाए। विशेषज्ञों के अनुसार एसडीएफ ढांचा, यूरोप के जीडीपीआर की तुलना में कहीं अधिक कड़ा और भारत-विशिष्ट अनुपालन बोझ जोड़ता है।

सीमा-पार डेटा ट्रांसफर: डीपीडीपी नियम सीमा-पार डाटा ट्रांसफर की अनुमति देते हैं, लेकिन सरकार के पास यह अधिकार होगा कि वह किसी विदेशी देश या संस्था पर प्रतिबंध लगा सके। जीडीपीआर की तुलना में यह व्यवस्था अधिक लचीली और कम खर्चीली मानी जा रही है, जिससे अंतरराष्ट्रीय डाटा प्रवाह आसान होगा।

****

Dainik Jagaran Page No-11

परिवारवाद की नियति

बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की करारी हार राष्ट्रीय जनता दल के लिए तो बड़ा झटका है ही, इस पराजय ने राजनीतिक परिवारों के भीतर बढ़ती महत्वाकांक्षाओं के टकराव को एक बार फिर सार्वजनिक किया है। राजद सुप्रीमो लालू यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य ने जिस तरह अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव और उनके दो करीबी नेताओं पर मुखर निशाना साधा है, वह लालू परिवार के अलावा राजद कार्यकर्ताओं के लिए भी एक बेहद कटु अनुभव है। रोहिणी ने न सिर्फ नाम लेकर कुछ लोगों की भूमिका पर सवाल खड़े किए, बल्कि राजनीति व परिवार से अलग होने का भी एलान कर दिया। गौरतलब है, रोहिणी पिछले लोकसभा चुनाव में सारण संसदीय क्षेत्र से पार्टी की उम्मीदवार थीं और करीब 13,600 मतों से चुनाव हार गई थीं। विधानसभा चुनाव से कुछ ही महीने पहले लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को भी पार्टी व परिवार से निकाल दिया गया था। इन सबसे यही संदेश गया है कि यह परिवार के भीतर एकाधिकार हासिल करने और उसे दूसरे सदस्यों द्वारा चुनौती देने का नतीजा है। जाहिर है, पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं के मनोबल पर इसका बुरा असर पड़ेगा, जबकि उन्हें इस वक्त एकजुटता की कहीं अधिक दरकार है।

यह सिर्फ एक राजनीतिक परिवार का मसला नहीं है, तमाम वंशवादी-व्यक्तिवादी दलों की यही विडंबना है। खासकर क्षेत्रीय दलों में यह विद्रूप कहीं अधिक दिखता है। तमिलनाडु, तेलंगाना से लेकर आंध्र, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जहां कहीं भी एक से अधिक सदस्य राजनीति में सक्रिय हैं, वहां महत्वाकांक्षाओं के टकराव शर्मनाक रूप से सामने आते हैं। उनमें से सबसे सशक्त सदस्य के साथ कार्यकर्ता लामबंद होते हैं, मगर आम अवाम के बीच उसकी नैतिक आभा जरूर मलिन पड़ जाती है। व्यक्तिवादी पार्टियों का भविष्य भी एक व्यक्ति के आस-पास घूमता है। ऐसे दलों के प्रमुख कभी अपना उत्तराधिकारी तैयार नहीं करते और न ही किसी को इतना मजबूत होने देते हैं कि वह उन्हें चुनौती दे सके। ऐसे में, उनके पतन के साथ दल के भविष्य पर प्रश्नचिह्न लग जाता है। ओडिशा का बीजू जनता दल इसका ताजा उदाहरण है। करीब 24 साल तक एकछत्र राज करने वाले बीजू जनता दल में नवीन पटनायक के अस्वस्थ होने के बाद एक बड़ा खालीपन पैदा हुआ है। इसकी तस्दीक नुआपाड़ा उप-चुनाव कर रहा है, जहां पार्टी तीसरे नंबर पर चली गई।

यह सिर्फ एक सियासी परिवार का मसला नहीं है, तमाम वंशवादी-व्यक्तिवादी दलों की यही विडंबना है। खासकर क्षेत्रीय दलों में यह विद्रूप कहीं अधिक दिखता है।

भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमी यही है कि राष्ट्रीय दल हों या क्षेत्रीय, उनमें आंतरिक लोकतंत्र की भारी कमी है। वे एक व्यक्ति या परिवार से अपनी समूची ऊर्जा बटोरते हैं। नतीजतन, उनके लिए पार्टी कार्यक्रम से अधिक अहम सत्ता में आना बन गया है और वे नैतिक-अनैतिक किसी भी रास्ते से बस शासन में पहुंचना चाहते हैं। ऐसे में, डेढ़ अरब लोगों का यह लोकतंत्र चंद राजनीतिक परिवारों और कुछ धनाढ्य लोगों के शिकंजे में फंसता जा रहा है। सत्ता-सदनों में करोड़पति-अरबपति प्रतिनिधियों की तादाद जिस तरह बढ़ रही है, उसे देखते हुए यह कहने में संकोच नहीं कि जल्द ही आम भारतीय सिर्फ मतदाता बनकर रह जाएंगे। मगर लोकतंत्र की सफलता सिर्फ चुनाव कराने और सरकार बनाने में निहित नहीं है, उसकी कामयाबी इस बात में है कि वह हाशिये के लोगों को भी जन-प्रतिनिधि बनने के लिए कितना प्रेरित करता है और उन्हें कितना समान अवसर मुहैया कराता है। हमारे लोकतंत्र को इस मामले में अभी लंबी दूरी तय करनी है।

Hindustan Page No-10

जनकल्याण से भी मिलता है वोट

सुरेंद्र किशोर
वरिष्ठ पत्रकार

राजद प्रमुख लालू प्रसाद अक्सर कहते थे कि वोट विकास से नहीं सामाजिक समीकरण से मिलते हैं। चुनाव ने इस धारणा को गलत साबित किया है और दिखाया है कि विकास और जनकल्याण से भी न केवल वोट मिलते हैं बल्कि चुनाव में शानदार जीत मिलती है।

बिहार विधान सभा का चुनाव नतीजा कुछ गैर राजग दलों को बड़ा सबक दे गया है। सबक यह है कि उन दलों की यह रणनीति अंततः विफल हो गई है कि 'सुशासन, विकास और समाज कल्याण से वोट नहीं मिलते, बल्कि सामाजिक समीकरण यानी जातीय और सांप्रदायिक जोड़-तोड़ से वोट मिलते हैं।'

इस सबक की सुगंध देश के बाकी हिस्सों में भी देर -सबेर फैल सकती है। अपने शासनकाल में राजद प्रमुख लालू प्रसाद अक्सर यह कहा करते थे कि 'विकास से वोट नहीं मिलते, बल्कि सामाजिक समीकरण से वोट मिलते हैं।' कहते हैं कि लालू सरकार ने विकास इसलिए भी नहीं किया क्योंकि लगता था कि विकास का अधिक लाभ वही तत्व उठा लेंगे, जो मंडल आरक्षण के विरोधी रहे हैं। उधर सपा नेता अखिलेश यादव पीडीए बनाकर उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ अन्य प्रदेशों के गैर राजग दलों का भी कमोबेश यही रुख-रवैया रहा है। बिहार विधान सभा चुनाव नतीजे के बाद अब उन्हें भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी या फिर वहां भी वही होगा जो बिहार चुनाव में हुआ है। जो दल या विश्लेषणकर्ता यह आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव की पूर्व संध्या पर महिलाओं के खाते में पैसे देकर राजग ने चुनाव जीता है, वे गत लोक सभा चुनाव में बिहार राजग की शानदार उपलब्धि को नजरअंदाज कर रहे हैं। साथ ही, वे नवंबर, 2024 में हुए उपचुनावों के जनादेश की भी अनदेखी कर रहे हैं। तब बिहार के चार विधान सभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुए थे। चारों पर राजग की जीत हुई थी। इनमें से तीन सीटें उपचुनाव से ठीक पहले महागठबंधन के पास थी। राजग ने दो सीटें राजद और एक सीट माले से छीन ली थी। राजद और माले से सीटें छीनना उससे पहले आसान काम नहीं माना जाता था। गत लोक सभा चुनाव में बिहार की कुल 40 सीटों में से 30 सीटें राजग को मिली थी। नवंबर, 2024 के बाद नीतीश सरकार ने ऐसा कोई जन विरोधी काम भी नहीं किया था, जिससे 2025 के विधान सभा चुनाव में राजग को हार का सामना करना पड़ता। ताजा जीत नीतीश सरकार की वर्षों से जारी सुशासन और अभूतपूर्व विकास की देन है। इसमें 2014 के बाद मोदी सरकार से मिल रही केंद्रीय मदद का भी भारी योगदान रहा है।

लंबे शासन काल के बावजूद नीतीश कुमार के खिलाफ न तो भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगा न ही परिवारवाद का। इन विरल गुणों के कारण भी आम लोगों में नीतीश सरकार की साख बनी रही। उधर, नरेन्द्र मोदी सरकार ने बिहार में भी लोगों पर जो अपनी सकारात्मक छाप छोड़ी है, उसका लाभ भी राजग को इस बार मिला। इस चुनाव प्रचार के दौरान खुद राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी 'जंगल राज' की याद दिला दी थी। उन्होंने सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने यह नारा लगा दिया था- 'शहाबुद्दीन अमर रहें-तसलीमुद्दीन अमर रहें।' उधर राजद के अनेक कार्यकर्ताओं ने कई बार खुले चुनाव मंचों से अपनी हरकतों और बोल वचन से 'जंगल राज' के दिनों की याद दिला दी। इन सबका नुकसान भी महागठबंधन को हुआ। महागठबंधन का यह प्रचार भी नहीं चला कि वोट चोरी हो रही है। जहां तक महिलाओं के बैंक खातों में सरकारी सहायता देकर वोट खरीदने का आरोप का सवाल है,उसका भी विपरीत असर राजग पर नहीं हुआ।

क्योंकि खुद कांग्रेस पार्टी दो अवसरों पर ठीक आम चुनावों से पहले लोगों के खातों में पैसे जमा करने का वायदा किया था। सन 2024 के लोक सभा चुनाव प्रचार अभियान के दौरान कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अनेक परिवारों को 'गारंटी कार्ड' दिए थे। उसमें प्रत्येक गरीब परिवार की एक महिला को एक लाख रुपये चुनाव के बाद देने का वादा किया गया था। वादा था कि हमारी सरकार बनेगी तो देंगे। सन 2019 के लोक सभा चुनाव से ठीक पहले भी राहुल गांधी ने मतदाताओं से वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद हमारी सरकार देश के बीस प्रतिशत जरूरतमंद परिवारों को हर साल 72 हजार रुपये देगी। खैर, कांग्रेस केंद्र की सत्ता में नहीं आई। पर, जिन राज्यों में कांग्रेस सत्ता में है, वे सरकारें ऐसी किसी योजना को कार्यान्वित कर रही है? ऐसा करने के लिए कांग्रेस की राज्य सरकारों को टैक्स चोरी रोक कर राजस्व बढ़ाना होगा। यानी गरीबों के लिए खजाने में पर्याप्त पैसे उपलब्ध होने चाहिए। पर यह काम कांग्रेसी सरकारों की अपेक्षा बिहार की नीतीश सरकार काफी बेहतर ढंग से करती रही है। जागरूक मतदाताओं ने इस फर्क को महसूस किया और जाना कि कांग्रेस का वादा छलावा मात्र है।

Dainik Jagaran Page No-7

महिलाओं–नीतीश की साझा समझ

हाल में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे हर तरह से अप्रत्याशित हैं। चुनावी विश्लेषण में यह समझना होगा कि राजग को यह जीत कैसे मिली। बिहार की राजनीतिक बनावट को समझने वाले यह जानते हैं कि बिहार का भूखंड विभिन्न क्षेत्रों में बंटा हुआ है। सबसे बड़ी विभाजन रेखा गंगा नदी है। इस पर राजनीति खास कर केंद्रीय और दक्षिण बिहार की राजनीति का कोई मेल उत्तर बिहार से नहीं है। भाषाई विविधता भी है, कहीं मगही, कहीं भोजपुरी तो कहीं मैथिली। अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग जातियों का वर्चस्व है और अलग किस्म की राजनीति भी है। तो ऐसा क्या हुआ विविधता से भरे बिहार में हमें एकपक्षीय नतीजा देखने को मिला। ऐसी क्या बात है कि दो दशक तक राज करने के बावजूद नीतीश कुमार के खिलाफ सत्ता विरोधी रूझान देखने को नहीं मिला। राजनीतिक विश्लेषक अब यह भी समझना चाहते हैं कि प्रो इनकंबेंसी बनती है तो कैसे। इस तरह के चुनाव नतीजों के पीछे महिला मतदाताओं का एकजुट होना बहुत महत्व रखता है। चुनाव में न सिर्फ महिला मतदाताओं ने रिकार्ड संख्या में वोट डाला बल्कि समझी जाने वाली बात यह है कि 2.47 करोड़ महिलाएं वोट देने आईं। यह संख्या पुरुषों से ज्यादा थी। आलोचकों ने यह भी कहा महिलाओं को चुनाव से ठीक पहले 10,000 रुपये का प्रलोभन देकर रिझाया गया लेकिन गहन विश्लेषण के बाद एक अच्छी समझ उभरती है वह यह है कि नीतीश कुमार की सरकार ने चुपचाप काफी लंबे समय से लड़कियों और महिलाओं को ग्रामीण बिहार में समाज के हाशिए से उठा कर मुख्यधारा में लाने का काम किया और यह सब राजनीतिक दावेदारी के बिना किया गया। 2005 में जब नीतीश कुमार एक स्थिर सरकार के मुख्यमंत्री बने, उसी समय उन्होंने यह समझा कि दुनिया में

मनीषा प्रियम
राजनीतिक विश्लेषक

नीतीश कुमार ने दो दशक के शासन में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए चुपचाप काम किया है। बिहार में महिलाएं अब अलग अलग क्षेत्रों में नेतृत्व करती हुई दिखती हैं। चुनाव नतीजों में भी महिलाओं और नीतीश की चुप्पी का सामाजिक साझापन दिखता है।

सबसे ज्यादा बच्चे अगर कहीं स्कूल से बाहर हैं तो वह बिहार है। इनमें सबसे ज्यादा पिछड़ी जाति के बच्चे और बच्चियां हैं। इन सब की समग्र समझदारी प्राप्त करने के लिए उन्होंने अधिकारियों की टीम को आंध्र प्रदेश भेजा। स्वर्गीय मदन मोहन झा बिहार के शिक्षा सचिव थे। आंध प्रदेश में रेजीडेंशियल ब्रिज कोर्स देखने के बाद यह समझ बनी कि बच्चियों को विशेष रूप से स्कूल की मुख्यधारा में लाना चाहिए। सकता। उन्होंने सरकार पर यह भार सौंपा कि ब्लाक स्तर पर शिक्षा की जो व्यवस्था थी वह गांव गांव लोगों के घरों में जाकर लोगों को समझाए और विशेष रूप से निचली जाति की बच्चियों को स्कूल लाया जाए। इसके बाद नीतीश कुमार ने बतौर मुख्यमंत्री एक साइकिल योजना की शुरुआत की जो एक तरह से कैश ट्रांसफर था। नीतीश कुमार का यह मानना था कि यदि राज्य साइकिल खरीदने और उसके वितरण में लग जाएगा तो फिर धांधली और गोरखधंधा होगा। इससे अच्छा है कि साइकिल के लिए परिवार को पैसा दिया जाए और परिवार के जन जाकर बच्चियों के लिए साइकिल खरीदें ओर बच्चियां साइकिल के लिए स्कूल आएं। साथ साथ पथ निर्माण विभाग ने बिहार में सड़कों का ताना बना बुना और कुछ ही वर्ष में छोटी छोटी बच्चियां साइकिल चलाते हुए स्कूल जाते हुए दिखीं। विश्व यह देख कर स्तब्ध रह गया कि जातीय व्यवस्था से दबे हुए बिहार में क्या हुआ कि दबे कुचले वर्गों की बच्चियां भी साइकिल पर चढ़ कर सड़कों पर उतर गईं। बच्चियों को यूनिफार्म का आवंटन भी किया गया। इस तरह से पर्दे के पीछे रहने वाली लड़कियां बच्चियां राज्य की कल्याणकारी नीतियों के चलते ही स्कूली शिक्षा की ओर उन्मुख हुईं। 2006 में ही नीतीश ने कर्पूरी ठाकुर के विजन को अमली जामा पहनाया और त्रिस्तरीय पंचायत में पिछड़ी जातियों और महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया। आने वाले दिनों में महिलाएं मुखिया चुनी गईं। वार्ड मेंबर बनीं। पंचायतों में सचिव और मेयर बनीं। कहीं न कहीं ग्रामीण व्यवस्था में महिलाएं भी नेतृत्व करते हुए देखी गईं। इन महिलाओं में अनेक पिछड़ी जातियों से थीं। इसके साथ ही 2013 में नीतीश कुमार ने पुलिस में कांस्टेबल से लेकर डीएसपी तक की भर्ती में महिलाओं को आरक्षण दिया। इसके साथ ही महिलाएं वर्दी में भी दिखने लगीं। मैं ऐसा दावा नहीं करती कि महिलाओं को लेकर कोई समता मूलक क्रांति हुई या सब कुछ बदल गया लेकिन परिवर्तन की लौ जलाई गई। चुनाव से पहले जीविका दीदी को मिले 10,000 रुपये भी नीतीश कुमार के लगातार किए गए प्रयासों में एक टापअप जैसा है, जो महिलाओं को आश्वस्त करता है कि उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे।

मुद्दा से संबंधित अपनी राय, सुझाव और प्रतिक्रिया mudda@jagran.com पर भेज सकते हैं। | 7 दैनिक जागरण | पटना, 17 नवंबर, 2025

हां 89% / 11% नहीं — क्या नीतीश कुमार का महिला सशक्तीकरण पर लगातार काम करना चुनाव में निर्णायक साबित हुआ?

हां 82% / 18% नहीं — क्या मतदाताओं ने विपक्ष के आर्थिक रूप से अव्यावहारिक लोकलुभावन वादों को खारिज कर दिया है?

बिहार: एकतरफा नतीजों के निहितार्थ

ऐतिहासिक मतदान के बाद बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे एकतरफा रहे हैं। नीतीश कुमार की अगुआई में राजग प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रहा है। बहुत सारे दूसरे फैक्टर के साथ महिला सशक्तीकरण के लिए नीतीश कुमार का पिछले 20 वर्षों से किया जा रहा प्रयास चुनाव नतीजों में निर्णायक बनकर उभरा है। फ्रीबीज की राजनीति के दौर में राजग सरकार ने इससे परहेज करते हुए वित्तीय मदद के जरिये महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने की पहल की है। ऐसा लग रहा है कि महिलाओं ने इस पहल पर सकारात्मक रूख दिखाया है। वहीं, मतदाताओं ने आर्थिक रूप से वहनीय न समझे जाने वाले लोकलुभावन वादों को खारिज कर दिया है। विपक्ष के लिए भी यह सोचने का समय है कि वह खुद को एक मजबूत विकल्प के तौर पर पेश करने के लिए क्या करे? इस एकतरफा जनादेश के निहितार्थ की पड़ताल ही आज का मुद्दा है...

अंधेरे से निकल कर विकास के उजाले में आया बिहार

बिहार दशकों से भारत के सबसे गरीब राज्य के रूप में जाना जाता रहा है और लगभग सभी सामाजिक-आर्थिक संकेतकों पर पिछड़ा रहा है। बिहार की पिछड़ी स्थिति के बावजूद, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुशासन के लिए एक प्रतिष्ठा अर्जित की है, जिसके कारण नीतीश को 'सुशासन बाबू' की उपाधि मिली है। नीतीश कुमार 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। अब तक के सामाजिक-आर्थिक संकेतकों का विश्लेषण दर्शाता है कि नीतीश के नेतृत्व में बिहार कितना आगे बढ़ गया है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के विभिन्न संकेतकों पर, 2005-06 से 2019-21 (नवीनतम उपलब्ध आंकड़े) तक, नीतीश के नेतृत्व में बिहार में राष्ट्रीय औसत की तुलना में तेज गति से सुधार हुआ है, जिससे राज्य उनके सत्ता संभालने के समय की तुलना में अखिल भारतीय जीवन स्तर के बहुत करीब पहुंच गया है।

बिजली: एनएफएचएस के आंकड़ों के अनुसार, 2019-21 तक, बिहार घरेलू विद्युतीकरण में राष्ट्रीय औसत के लगभग बराबर पहुंच गया था। राज्य में 96 प्रतिशत परिवारों ने बिजली को प्रकाश का अपना मुख्य स्रोत बताया, जबकि पूरे भारत में यह आंकड़ा 97 प्रतिशत था। 2005-06 में, राज्य के केवल चार में से एक घर में ही बिजली थी, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा लगभग दो-तिहाई था। इसका अर्थ है कि लगभग 15 वर्षों में, बिहार की विद्युतीकरण दर लगभग 250 प्रतिशत बढ़ी, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर यह वृद्धि 42 प्रतिशत रही, जो बिहार के कम शुरुआती आधार और इस अवधि में ग्रामीण विद्युतीकरण के तीव्र विस्तार, दोनों का प्रतिबिंब है। बिजली की व्यवस्था के लिए बुनियादी ढांचे की व्यापक स्थापना को नीतीश के कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियों में से एक माना जाता है।

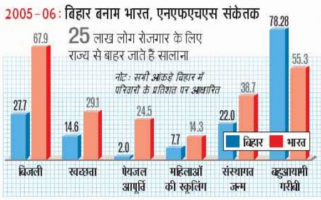

2005-06: बिहार बनाम भारत, एनएफएचएस संकेतक

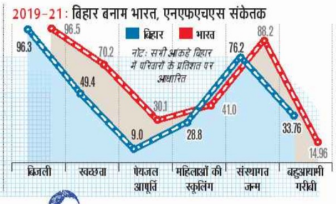

2019-21: बिहार बनाम भारत, एनएफएचएस संकेतक

दस वर्ष से अधिक स्कूली शिक्षा प्राप्त करने वाली महिलाएं

सत्ता में पिछले दो दशकों में, नीतीश ने जाति और वर्ग की सीमाओं से परे एक ऐसे वर्ग को बड़ी सावधानी से विकसित किया है। यह वर्ग है महिलाओं का। उनकी महिला-केंद्रित पहलों में से एक पहली और सबसे प्रमुख पहल 2006 में शुरू की गई मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना थी, जिसके तहत स्कूली लड़कियों को मुफ्त साइकिलें प्रदान की गईं। बिहार में 10 साल से ज्यादा स्कूली शिक्षा प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या 2019-21 तक 3.5 गुना बढ़कर 29 प्रतिशत हो गई। 2019-21 में अखिल भारतीय स्तर पर यह संख्या 41 प्रतिशत के साथ बेहतर थी, लेकिन बिहार की तुलना में यह वृद्धि धीमी रही है, यानी तीन गुना से भी कम।

संस्थागत जन्म

किसी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में होने वाले जन्मों का अनुपात सार्वजनिक स्वास्थ्य योजनाओं की प्रभावशीलता और चिकित्सा अवसंरचना पर व्यय, दोनों को दर्शाता है। 2005-06 में, बिहार में केवल 22 प्रतिशत जन्म संस्थागत थे। 2019-21 तक, यह बढ़कर 76 प्रतिशत हो गया है, जो तीन गुना से भी अधिक वृद्धि है। हालांकि, भारत में संस्थागत जन्म दर 2005-06 में 39 प्रतिशत से बढ़कर 2019-21 में 89 प्रतिशत हो गई है, जो बहुत धीमी गति से बढ़ी है।

स्वच्छता: एनएफएचएस के अनुसार, किसी घर में बेहतर स्वच्छता सुविधा तभी मानी जाती है जब वह ऐसे शौचालय का उपयोग करता है जो अपशिष्ट को मानव संपर्क से सुरक्षित रूप से अलग करता है। 2019-21 तक, बिहार में लगभग आधे परिवारों ने स्वच्छता के बेहतर स्रोत तक पहुंच होने की घोषणा की, जबकि पूरे भारत में 10 में से सात परिवारों ने यह घोषणा की। 2005-06 से, जब बिहार लगभग 15 प्रतिशत पर था, राज्य में स्वच्छता तक पहुंच तीन गुना से अधिक बढ़ गई है, जबकि भारत में यह वृद्धि 2.5 गुना से भी कम रही है। बेहतर स्वच्छता सुविधा तक पहुंच 2019-21 में 30 प्रतिशत से बढ़कर 70 प्रतिशत से अधिक हो गई है।

पेयजल: जब नीतीश ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब बिहार के लगभग दो प्रतिशत लोगों के घरों, आंगन या प्लाट में पाइप से पेयजल उपलब्ध था। 2019-21 में यह संख्या बढ़कर नौ प्रतिशत हो गई। अधिकांश (83 प्रतिशत) लोगों को अभी भी ट्यूबवेल या बोरवेल से काम चलाना पड़ता है। देशभर में एक-तिहाई (33 प्रतिशत) परिवारों ने बताया कि 2019-21 तक उनके घरों में पाइप से पेयजल की सीधी पहुंच थी। 2005-06 में यह संख्या चार में से एक परिवार तक थी। इस प्रकार, बिहार ने राष्ट्रीय औसत से तेज प्रगति की है, लेकिन वास्तविक पहुंच के मामले में यह अभी भी बहुत पीछे है।

4.0% थी बिहार की जीडीपी में औद्योगिक हिस्सेदारी वर्ष 2000 में

21.5% हो गई है वर्तमान में बिहार की जीडीपी में औद्योगिक हिस्सेदारी

10.2% रही है बिहार की सालाना वृद्धि दर पिछले 20 वर्षों के दौरान

9.2% रही है राज्य की जीडीपी की औसत वृद्धि दर 2022 के बाद

25,000 करोड़ रुपये सालाना अपने घर भेजते हैं बिहार के प्रवासी श्रमिक

जागरण रिसर्च

नोट: कुछ संकेतकों पर बिहार की वृद्धि प्रभावशाली है, लेकिन उच्च प्रतिशत वृद्धि को इस संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए कि राज्य का बेस बहुत कम था और अन्य राज्यों की तुलना में यहां अभी विकास के मोर्चे पर काफी काम बाकी है।

आरक्षण में क्रीमी लेयर

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने अनुसूचित जाति आरक्षण में क्रीमी लेयर के सिद्धांत को लागू करने की आवश्यकता को लेकर जो विचार व्यक्त किए, वे नए नहीं हैं। वे इसके पहले भी ऐसा कह चुके हैं। तथ्य यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले अनुसूचित जाति-जनजाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण को मान्यता प्रदान की थी। सुप्रीम कोर्ट की इस पीठ में न्यायाधीश गवई भी थे। स्पष्ट है कि वे इसके प्रबल पक्षधर हैं कि क्रीमी लेयर का जो सिद्धांत अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी आरक्षण में लागू है, वही अन्य आरक्षित वर्गों यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण में भी लागू किया जाए। यह स्वाभाविक है कि उनके इस कथन पर अलग-अलग राय सामने आएगी और एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के उनके विचार की आलोचना भी होगी, लेकिन न्याय और नीति यही कहती है कि आरक्षण की व्यवस्था को इस तरह लागू किया जाए कि पात्र लोगों को ही उसका लाभ मिलना सुनिश्चित हो सके। ऐसा तब होगा, जब वंचित वर्गों के समर्थ यानी क्रीमी लेयर वाले लोगों को आरक्षण का लाभ लेने से रोका जाएगा। एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर की व्यवस्था बनाए जाने के पक्ष में न्यायाधीश गवई ने यह बिल्कुल सही कहा कि आइएएस और गरीब मजदूर के बेटों को एक जैसा नहीं माना जा सकता। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि आरक्षण का उद्देश्य वंचित एवं पिछड़े तबकों के उन लोगों के उत्थान के विशेष प्रयत्न किए जाना है, जो वास्तव में सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। आम तौर पर सामाजिक रूप से ऐसे पिछड़े लोग आर्थिक रूप से भी कमजोर होते हैं। आरक्षण में क्रीमी लेयर के सिद्धांत को लागू करने के विरोध में यह तर्क दिया जाता है कि आरक्षित वर्ग के किसी व्यक्ति के उच्च पद पर पहुंच जाने के बाद भी कई बार उसे उपेक्षा या भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इस तर्क को खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन इससे यही तो सिद्ध होता है कि आरक्षण सामाजिक विषमता और आर्थिक असमानता दूर करने का एकमात्र उपाय नहीं है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि देश में कमजोर वर्गों के तमाम लोग बिना आरक्षण सामाजिक-आर्थिक रूप से सक्षम बने हैं। आरक्षण वास्तव में पात्र यानी कमजोर लोगों के ही उत्थान में सहायक बने, इसके लिए अन्य उपायों के साथ जैसे एससी-एसटी आरक्षण में उपवर्गीकरण को मान्य किया गया, वैसे ही क्रीमी लेयर के सिद्धांत को भी अपनाया जाना चाहिए। इसी क्रम में यदि आरक्षित वर्गों के वे समर्थ लोग जो आरक्षण का लाभ लेकर उच्च पदों पर पहुंच चुके हैं, स्वेच्छा से उसका परित्याग करें तो सकारात्मक माहौल का निर्माण होगा और मुख्य न्यायाधीश ने जो विचार व्यक्त किए, उन्हें और बल मिलेगा।

Dainik Jagaran Page No-6

डांवाडोल होती अमेरिकी अर्थव्यवस्था

डा. सुरजीत सिंह

डोनाल्ड ट्रंप की मनमानी 'अमेरिका प्रथम' की नीति स्वयं वहां की आर्थिक नींव को कमजोर कर रही है

उलटा पड़ता टैरिफ वार का दांव ● फाइल

अमेरिका प्रथम की मुहिम के साथ चलने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हर निर्णय चाहे वह अंतरराष्ट्रीय समझौता हो, व्यापार नीति हो या सुरक्षा निर्णय दूसरों पर थोपने की नीति पर केंद्रित रहता है। वैश्वीकरण की गति को धीमा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने भारत सहित विश्व के अन्य देशों पर टैरिफ लगाकर व्यापार युद्ध की स्थिति पैदा कर दी। ट्रंप प्रशासन उन अनेक बहुपक्षीय संस्थाओं की या तो फंडिंग कम कर रहा है या उनसे बाहर निकलने की धमकियां देकर उनकी भूमिका को कमजोर करने का प्रयास कर रहा है, जो कथित तौर पर अमेरिका के हित में कार्य नहीं कर रही हैं। उनकी इस नीति का असर केवल बाहरी दुनिया तक सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिका के भीतर भी इसका व्यापक आर्थिक और सामाजिक प्रभाव पड़ रहा है। व्यापार युद्ध ने न केवल विदेशी व्यापार को झटका दिया है, बल्कि अमेरिका के घरेलू बाजार में मूल्य वृद्धि को भी बढ़ावा दिया है।

अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के प्रतिरोध में अन्य देशों द्वारा लगाए जाने वाले जवाबी टैरिफ से अमेरिकी उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति प्रभावित हो रही है। अमेरिका में न सिर्फ रोजमर्रा की वस्तुएं, बल्कि इलेक्ट्रानिक उपकरण, खिलौने, कपड़े, मशीनें आदि के महंगे होने से अमेरिका में मार्च 2025 के बाद से आयातित सामान की कीमतें लगभग चार प्रतिशत बढ़ी हैं, जबकि घरेलू सामान की कीमतें लगभग दो प्रतिशत बढ़ गई हैं। बढ़ती महंगाई को देखते हुए ट्रंप ने 200 से अधिक वस्तुओं पर से टैरिफ कम करने का फैसला किया है। अमेरिका में उद्योगों के लिए कच्चा माल महंगा होने से बढ़ती उत्पादन लागत से नौकरियां ही नहीं घट रही हैं, बल्कि किसानों की आय पर भी गहरा असर पड़ रहा है। चीन, कनाडा और यूरोपीय देशों द्वारा प्रतिशोध में लगाए गए टैरिफ के कारण अमेरिकी सोया और मक्का जैसी कृषि वस्तुओं की मांग घटी है, जिससे किसानों की आय में गिरावट आने से सरकार को अरबों डालर की सब्सिडी देनी पड़ रही है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर इसके दुष्परिणाम अब स्पष्ट दिखने लगे हैं। येल विश्वविद्यालय के बजट अध्ययन केंद्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, टैरिफ और विदेशी प्रतिकारात्मक करों के कारण 2025 में अमेरिका की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर लगभग 0.9 प्रतिशत अंक कम हो रही है। टैरिफ नीतियों के कारण एक आम अमेरिकी परिवार को औसतन 3,800 डालर तक का नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं पेन-वार्टन बजट माडल का विश्लेषण बताता है कि ट्रंप की व्यापारिक नीतियों के कारण अमेरिका की जीडीपी दीर्घकाल में लगभग छह प्रतिशत तक घट सकती है और मजदूरी में लगभग पांच प्रतिशत की गिरावट आ सकती है।

ओईसीडी ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा है कि यदि टैरिफ और एकतरफा व्यापार नीतियां जारी रहीं तो 2026 तक अमेरिका की जीडीपी वृद्धि दर 1.6 प्रतिशत तक गिर सकती है। यह गिरावट न केवल अमेरिका, बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था के लिए भी चिंता का कारण होगी, क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था वैश्विक व्यापार का मुख्य इंजन है। आम अमेरिकी इस नीतिगत बदलाव की सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं। उच्च मूल्य, घटती आय और रोजगार के अवसरों में कमी ने अमेरिकी सपने की धारणा को कमजोर किया है। ट्रंप की मनमानी नीतियों का अमेरिका में विरोध भी शुरू हो चुका है। एक हालिया सर्वेक्षण में लगभग 55 प्रतिशत अमेरिकी नागरिकों ने कहा कि ट्रंप अब एक खतरनाक तानाशाह की तरह व्यवहार कर रहे हैं। वह अपने विरोधियों को निशाना बनाने के लिए सरकारी संस्थाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। यही कारण है कि उनके नेतृत्व में अमेरिका का लोकतांत्रिक ढांचा पहले की अपेक्षा अधिक विभाजित हो गया है। ''हैंड्स आफ'' और ''नो किंग'' जैसे आंदोलनों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिकी जनता अब अधिक हस्तक्षेप और केंद्रीकृत शक्ति के विरोध में एकजुट हो रही है।

डगमगाती अमेरिकी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ट्रंप की राष्ट्रवादी नीतियां और अधिक चुनौतीपूर्ण साबित हो रही हैं। ''अमेरिका प्रथम'' के उनके नारे ने जहां कुछ समय के लिए घरेलू उद्योगों को सहारा दिया, वहीं वैश्विक व्यापारिक साझेदारियों से दूरी ने अमेरिकी बाजार पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। अंतरराष्ट्रीय निवेश घटा है, निर्यात पर दबाव बढ़ा है और डालर की अस्थिरता से आयात महंगा हुआ है। इस बीच बेरोजगारी में वृद्धि और उपभोक्ता कीमतों में लगातार बढ़ोतरी ने मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति को कमजोर कर दिया है। प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार, लगभग 60 प्रतिशत अमेरिकियों का मानना है कि ट्रंप की नीतियों से आर्थिक असमानता बढ़ी है, जबकि श्रमिक वर्ग को उनके वादों का कोई वास्तविक लाभ नहीं मिला। आर्थिक विश्लेषकों के अनुसार, ट्रंप की संरक्षणवादी नीतियों ने अमेरिका की उत्पादन क्षमता को सीमित कर दिया है, जिससे नई नौकरियां सृजित होने के बजाय उद्योगों में छंटनी बढ़ी है। वित्तीय अस्थिरता और महंगाई ने अमेरिकी जनता की चिंता को गहरा किया है।

ट्रंप का राष्ट्रवाद सिर्फ राजनीतिक ध्रुवीकरण ही नहीं, बल्कि आर्थिक असंतुलन का कारण भी बनता जा रहा है। अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के लिए अपनाई गई नीतियां दीर्घकाल में अमेरिका की आर्थिक स्थिरता और वैश्विक विश्वसनीयता, दोनों को कमजोर कर रही हैं। अगर यही रुझान जारी रहा तो ''अमेरिका प्रथम'' की नीति स्वयं अमेरिका की आर्थिक नींव को हिला सकती है।

(लेखक अर्थशास्त्री हैं)
response@jagran.com

Dainik Jagaran Page No-6

आतंकवाद नहीं, जिहादी हिंसा

शंकर शरण

जिहादियों को आतंकी कहना अपने को भरमाना है। राजनीतिक-बौद्धिक वर्ग को तथ्य-आधारित समझ की आवश्यकता है

कई दशकों से जिहादी हिंसा पर इस कहावत के उलट काम किया जा रहा है कि जहां काम आवे सुई, कहां करे तलवार। जो काम सुई का है, वैचारिक-शैक्षिक संघर्ष का है, उसे तलवार, सैन्य-प्रहार आदि से हराने की कोशिश हो रही है। लोकतांत्रिक विश्व आत्म-प्रवंचना में है। लिहाजा आतंक बरपाने वाले नए-नए दस्ते, संगठन, सरगना इसलिए आते रहते हैं, क्योंकि उन्हें मौत का, तलवार का भय ही नहीं है। केवल तलवार उन पर निष्फल भी रहती है। जिसे आतंकवाद कहा जाता है, उसे आतंकी खुद जिहाद कहते हैं और अपने को मुजाहिदीन। भारत में एक संगठन का नाम ही इंडियन मुजाहिदीन था। इसने लखनऊ, वाराणसी, जयपुर, दिल्ली, मुंबई आदि शहरों पर अनेक बम-विस्फोट किए, जिनमें सैकड़ों नागरिक मारे गए। जिहाद की संज्ञा भारत में सैकड़ों वर्षों से बार-बार गूंजती रही है। गजनवी से लेकर बाबर जैसे बड़े-बड़े हमलावरों, सुल्तानों, बादशाहों तथा मौदूदी, इकबाल जैसे बड़े-बड़े आलिमों के मुंह और कलम से। फिर भी हमारा राजनीतिक-बौद्धिक वर्ग जिहाद पर चुप रहता है। वह उससे मुकाबला कैसे कर सकता है, जिससे आंख मिलाकर देखने में भी उसे संकोच है?

यदि मुजाहिदीनों द्वारा की गई हिंसा और आतंक का मुकाबला करना है तो वास्तव में जिहाद का सामना करना होगा। उसे उग्रवाद, आतंकवाद, विकृति आदि नाम देना झूठे उपायों की ओर ले जाता है। इसे अफगानिस्तान-पाकिस्तान में अमेरिकी विफलता में बड़े पैमाने पर देख सकते हैं। एक संगठन के बाद, दूसरे पैदा हो जाते हैं। एक सरगना के बाद दूसरा आ जाता है। एक भारतीय इमाम ने कहा था, एक ओसामा मरेगा, तो सौ पैदा होंगे। जिस विश्वास से उन्होंने ऐसा कहा था, उस पर विचार और चोट करनी चाहिए तब समाधान मिलेगा। जिहाद से अनजान लोग ही जिहादियों का सबसे बड़ा कवच हैं। जिहाद का सिद्धांत मानवता को दो हिस्से में बांटकर देखता है-इस्लाम मानने वाले और नहीं मानने वाले। इसी से इस सिद्धांत की दोहरी नैतिकता बनती है। मुस्लिम के साथ एक व्यवहार और काफिरों के साथ दूसरा। इसी से 'दारुल-इस्लाम' (जहां मुसलमानों का शासन हो) और 'दारुल-हरब' (जहां काफिरों का शासन हो) की धारणा है। इसी कारण यहूदियों से कहा गया था कि सारी दुनिया केवल मुसलमानों के लिए है और वे जान बचाने को इस्लाम कबूल करें। यही दावा राजनीतिक इस्लाम है और इसे लागू करने की गतिविधि जिहाद है। इतिहास को झुठलाने की मांग करने से लेकर सब पर शरीयत लादने, हलाल थोपने तक उसके असंख्य

लाल किले के निकट धमाके वाली जगह की जांच करती पुलिस ● एएफपी

शांतिपूर्ण रूप हैं। जिहाद सर्वमुखी युद्ध है। सहीह बुखारी में जिहाद संबंधी दो प्रतिशत हदीस कुछ कामों को जिहाद के बराबर बताते हैं, किंतु बाकी ९८ प्रतिशत हदीस हथियारबंद हिंसा से संबंधित हैं। हथियारबंद जिहाद ने ही राजनीतिक इस्लाम को सारी सफलता दी है। भारत के विगत हजार वर्ष में इसे असंख्य बार होता देख सकते हैं। मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर हमले से लेकर मुस्लिम लीग के डायरेक्ट एक्शन, पाकिस्तान बनने और कश्मीर से हिंदुओं के सफाए तक यदि कोई शब्द और कर्म समान मिलता है तो वह है जिहाद और हिंसा। जिहाद में एक पूरी मानसिकता और जीवनशैली है। जिहाद के बारे में प्रामाणिक जानना चाहिए। विशेषकर उन्हें, जिनके विरुद्ध जिहाद का स्थाई आह्वान है और जो इसे सदियों से झेल रहे हैं। बाबर ने भी जिहाद ही लड़ा था। 'बाबरनामा' में भारत पर हमले को जिहाद कहा गया है। बाबर ने खुद को फख्र से 'गाजी' यानी जिहाद लड़ने वाला कहा था। बाबर से लेकर इंडियन मुजाहिदीन तक उन्हीं स्रोतों को अपना मार्गदर्शक मानते हैं, जो मूल इस्लामिक स्रोत हैं। उनके सभी विश्वास, प्रेरणाएं, आदर्श इन्हीं से निःसृत होते हैं। इसीलिए राजनीतिक इस्लाम का रिश्ता बाकी दुनिया से जिहाद या अस्थाई शांति का है। उसके सिद्धांत में कोई तीसरी स्थिति नहीं बताई गई है।

जिहादियों को आतंकवादी कहना अपने को भरमाना है। हमारे राजनीतिक-बौद्धिक वर्ग को तथ्य-आधारित समझ की आवश्यकता है। तब साफ दिखेगा कि जिहाद का सिद्धांत किन-किन बिंदुओं पर कमजोर है, वहीं पर उसे चुनौती देकर हराया जा सकता है। जिहाद को हराना मुख्यतः विचार एवं शिक्षा का क्षेत्र है। इस्लामी दावों, सिद्धांतों का खुला, वैज्ञानिक परीक्षण करके खंडन करना तथा सारी बातें शिक्षा और मीडिया के माध्यम से घर-घर पहुंचाना। इसके प्रति काफिरों की गफलत में ही जिहादी आतंक रूपी तोते की जान छिपी है। राजनीतिक इस्लाम के प्रति सबका भ्रमित रहना ही जिहाद की ताकत है। इसे इस्लामी नेता बखूबी जानते हैं। इसीलिए अमेरिकी मिसाइलों से ज्यादा तसलीमा नसरीन जैसी लेखिकाओं से डरते हैं। वे काफिरों को भ्रमित रखने के लिए दोहरी नैतिकता के अपने सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। उन्हें इस्लामी दावों का झूठा, मीठा अर्थ बताते रहते हैं, जो मुसलमानों को बताए गए अर्थ से भिन्न होता है। इस छल के लिए भी उनके पास एक शब्द है, 'तकिया'। सहीह बुखारी में कहा गया है, ''जिहाद छल है (4:52:268)''-जिहाद इज डिसीट।

मुस्लिम ब्रदरहुड संगठन ने पूरी दुनिया में मिथ्या-प्रचार का व्यवस्थित वैचारिक तंत्र चला रखा है। जिसमें वे काफिर, जिहाद, दारुल-हरब, जिम्मी, हलाल, शरीयत आदि के बारे में झूठे तर्क फैलाते हैं, ताकि गैर-मुस्लिम सरकारें, बुद्धिजीवी, मीडिया आदि अनजान रहें, बल्कि इस्लामियों का बचाव भी करें। जब भी कोई सच बात रखी जाती है तो इस्लामी नेता नाराजगी दिखाते हैं। उसे इस्लाम को बदनाम करना कहकर, धमकी देकर बंद करवाया जाता है, जबकि ठीक वही बात सारे मुजाहिदीन ठसक से कहते हैं। रिलीजन इस्लाम का बहुत छोटा अंश है, उससे काफिरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस्लामी मतवाद का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा राजनीतिक है, जिससे काफिर गाफिल रहते हैं। फलतः जिहाद की मानसिकता अबाधित रहती है। उसे हराना ही असली कर्तव्य है। वह मुख्यतः शैक्षिक कार्य है। इसीलिए जिहादी आतंक से लड़ाई मुख्यतः तलवार की नहीं, सुई की है।

(लेखक राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)
response@jagran.com

Dainik Jagaran Page No-6

अखबारी कागज पर खाना खाकर बीमारी बुलाते लोग

यहां स्कैन करें

पंकज चतुर्वेदी | वरिष्ठ पत्रकार

हाल ही में मध्य प्रदेश के एक सरकारी स्कूल के बच्चों को मिड-डे मील कागज पर परोसने को लेकर काफी विवाद हुआ। भारत में 'स्ट्रीट फूड' संस्कृति हमारी जीवन-शैली का एक अभिन्न अंग है। गरमागरम समोसे, कुरकुरे पकौड़े, चटपटी चाट हो या नमकीन- इन व्यंजनों का आकर्षण किसी से छिपा नहीं है। लेकिन एक आदत है, जो इस आकर्षण पर एक गहरे काले धब्बे के समान है : अखबार या मुद्रित कागज में पकवानों को लपेटना या परोसना। यह पुराना, सहज व सस्ता चलन, जिसे हम सामान्य बात मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, वास्तव में हमारे स्वास्थ्य के लिए गंभीर और अनसुना संकट है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, यानी एफएसएसएआई ने बार-बार इस चलन के खिलाफ कठोर चेतावनी जारी की है। यहां तक कि खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम- 2018 के तहत इसे प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका पालन आज भी एक बड़ी चुनौती है।

रंगीन छपे कागजों में खाने-पीने की चीजों को लपेटने का चलन असल में उपभोक्ताओं के शरीर में धीमा जहर घोलने का काम करता है।

आजकल के अखबार केवल काली स्याही से नहीं छपते, इसे रंगीन बनाते हैं बहुत से जहरीले रसायन। हालांकि, ये रसायन शब्दों और छवियों को कागज पर चिपकाने में मदद करते हैं। खनिज तेल लगभग सभी मुद्रण स्याही में पाए जाते हैं, विशेष रूप से इनमें मिनरल ऑयल हाइड्रोकार्बन का उपयोग होता है। एफएसएसएआई के अनुसार, इन मिनरल ऑयल में से कुछ कार्सिनोजेनिक, यानी कैंसर पैदा करने वाले होते हैं। इनमें पॉली साइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन होता है, जो त्वचा, फेफड़े और मूत्राशय के कैंसर का बड़ा कारक है। यदि बच्चे नियमित रूप से इस तरह की स्याही वाले कागज पर खाते हैं, तो उनका विकास देर से होता है और वे एकाग्रता संबंधी समस्याओं या सीखने की कठिनाइयों के शिकार हो सकते हैं। गौर कीजिए, कागज पर खाने की चीजें परोस देने का संकट दूरस्थ अंचलों में अधिक है और वहीं पर बच्चों में स्कूल छोड़ने की संख्या अधिक है।

इस तरह के छपे हुए कागज में एक और खतरनाक रसायन होता है- बीपीए (बिस्फेनॉल ए), जो हमारे हार्मोन पर हमला करता है। इसे लड़कियों में समय से पहले पीरियड आने और पुरुषों में बांझपन से जोड़ा गया है। स्याही का एक और घटक, थैलियम भी हार्मोन के साथ छेड़छाड़ करने वाला तत्व माना जाता है। सन् 2023 में शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के एक अध्ययन में पाया गया कि युवाओं में ऑक्सीडेटिव तनाव बढ़ रहा है, जिसका बड़ा कारण जहरीली स्याही का गरम खाद्य पदार्थों से मिल जाना है।

अधिकांश अखबार री-साइकिल किए गए कागज पर छापे जाते हैं, जिसे बनाने की प्रक्रिया पहले ही अस्वच्छ होती है। फिर प्रिंटिंग प्रेस से होते हुए विक्रेता तक पहुंचने में अखबार कई सतहों, हाथों और धूल-मिट्टी के संपर्क में आते हैं। ऐसे में, जब इनमें भोजन परोसा जाता है, तो बैक्टीरिया खाने में चले जाते हैं, जिससे खाद्य विषाक्तता, गंभीर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल संक्रमण और डायरिया जैसी समस्याएं हो सकती हैं। बच्चों और बुजुर्गों पर इसका प्रभाव बहुत अधिक होता है। सबसे बड़ी बात यह कि स्याही से उपजे जहरीले तत्व आपको न स्वाद में, न गंध में महसूस होते हैं, और न ही इस बारे में व्यापक जागरूकता है। इसका बुरा असर धीरे-धीरे सामने आता है। इसकी शुरुआत पेट की समस्याओं से होती है, जैसे एसिडिटी या मरोड़ उठने के रूप में। फिर चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग होने के अलावा हार्मोन के असंतुलन से जुड़े कई रोग भी शरीर में घर कर जाते हैं। समय के साथ-साथ ऐसे रोग बढ़ते जाते हैं।

जाहिर है, छपे हुए कागज पर खाने का सामान बेचना एक आदत बन चुका है, जिसका अभी तक किसी ने विरोध किया नहीं, वरना इस पर पाबंदी के लिए किसी कानून की जरूरत नहीं है। अखबार कहानियां सुनाते हैं। मगर जब उसे हमारे खाने में लिपटा जाता है, तो वह उस कहानी का हिस्सा बन जाता है, जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। स्वस्थ भारत की दिशा में यह एक छोटा, पर महत्वपूर्ण कदम है कि हम जहर लपेटने की इस आदत को तुरंत त्याग दें। ग्राहकों और विक्रेताओं की सामूहिक जिम्मेदारी ही हमें इस 'साइलेंट हेल्थ इमरजेंसी' से बाहर निकाल सकती है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)